रोहतक
रविवार 25 जनवरी 2026
माघ मास, शुक्ल पक्ष,
सप्तमी वर्ष : 29, अंक : 357
पृष्ठ : 16 मूल्य : 3.50

मौसम
अधि. 17.4
न्यून. 1.6

हरिभूमि

हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

09 सीरीज जीत की दहलीज पर भारत, किशन के प्रदर्शन से संजू पर बढ़ा दबाव

haribhoomi.com

K.R. MANGALAM
World School
Bahadurgarh

Where Curiosity Grows into Confidence
Affiliated to CBSE

ENGAGE. LEARN. INNOVATE.

ADMISSIONS OPEN
Nursery to Grade IX & XI
(Play Group Also Available)
2026-27

Bond & Beyond Carnival
Celebrating International Peace & Trust
31st Jan 2026 | 10:00 AM to 7:00 PM
Annual Presentation | Talk Show | Gallery Walk
Fun & Games | Shopping Arcade | Food Fiesta
Live DJ | Competitions
"Lucky Draw Prizes include Electronics, Kitchenware and other exciting utility essentials"
Price: 200/-
Scan for Registration

Discover | Create | Perform

At K.R. Mangalam World School, Bahadurgarh, activities are an essential part of everyday learning. Through sports, creative expression and hands-on experiences, we help students build confidence, teamwork and life skills while keeping learning energetic, joyful and meaningful.

Sports & Physical Activities
- Outdoor sports like football, cricket, basketball and athletics
- Indoor games including chess, badminton and skating
- Focus on fitness, stamina and discipline
- Encourages teamwork and healthy competition

Creative & Expressive Activities
- Art, music, dance and theatre sessions
- Debate, public speaking and storytelling platforms
- Builds confidence and self-expression
- Nurtures creativity and emotional growth

Experiential & Skill-Based Activities
- Project-based and learning-by-doing activities
- STEAM and robotics-based challenges
- Programmes that build confidence and resilience
- Develops problem-solving and critical thinking
- Prepares students with real-world skills

The KRM Legacy of Excellence

40,000+ Students Studying | 50,000+ Alumni Members | 4,000 Faculty On Board

K.R. Mangalam stands as a trusted name in education. Our seamless admission process, modern infrastructure, and value-driven philosophy empower every learner to excel and lead with purpose.

Ranked No. 1
INNOVATORS CATEGORY
BY TIMES SCHOOL SURVEY 2025

admission@krmangalambahadurgarh.com
www.krmangalambahadurgarh.com
Sector 2, Near Gauri Shankar Mandir, Bahadurgarh, Haryana 124507

9549899503
The school is open for admissions on all days

G.K.- II | Vikaspuri | Kailash Colony | Paschim Vihar | Vaishali | Greater Noida | Faridabad | Gurugram | Bahadurgarh | Panipat | G.K.- I (IB) | Lucknow | Indirapuram

खबर संक्षेप

न्याय और सेवा के प्रतीक थे राजिंदर प्रसाद : स्पीकर

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि स्वर्गीय राजिंदर प्रसाद का जीवन न्याय, अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण रहा। वे न केवल एक उत्कृष्ट न्यायाधीश थे, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका आचरण समाज के लिए प्रेरणा बना। करनाल के कर्णेश्वर मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय राजिंदर प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि न्यायिक सेवा के दौरान उनके निर्णयों में कानून के साथ-साथ नैतिकता और मानवता का संतुलित समावेश दिखाई देता था।

निकाय चुनाव को लेकर भाजपा तैयार : बड़ौली

चंडीगढ़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जहां-जहां चुनाव होने हैं वहां-वहां पर सात मंत्रियों के साथ-साथ बड़े नेताओं की ड्यूटियां लगाई है। बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से चुनाव जीतने का दावा करती रही है, लेकिन जनता केवल बीजेपी को ही लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है।

चार्जशीट के बाद बिना जांच सजा देना अवैधः हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी संजीव आनंद को बड़ी राहत देते हुए विभाग द्वारा वर्ष 2015 से 2024 तक पारित सभी दंडात्मक आदेशों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट कहा है कि जब किसी कर्मचारी को मेजर पेनल्टी (बड़ी सज़ा) की चार्जशीट दी जाती है, तो बिना नियमित विभागीय जांच कराए, उस पर माइनर पेनल्टी (छोटी सजा) भी नहीं थोपी जा सकती। ऐसा करना कानून के स्थापित सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है।हाईकोर्ट ने निगम को निर्देश दिया है कि संजीव आनंद को उनकी अवैध रूप से रोकी गई सभी सेवा लाभों की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तीन माह के भीतर अदा की जाए।

उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद गठित

चंडीगढ़। हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद गठित कर दी है। मुख्यमंत्री परिषद की कमान संभालेंगे। श्रम मंत्री अनिल विज के साथ 20 सदस्यीय परिषद में छह विभागों के प्रशासनिक सचिव और उद्योगपतियों तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में उद्योग और श्रम को एक-दूसरे का पूरक मानते हुए पहल की है।

भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष, राज्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक हर भूमिका में स्वयं को साबित कर चुके नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अनूठी पहचान बना रहे हैं। आमजन सा दिखने वाला यह मुख्यमंत्री आज जब अपने जीवन के 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो प्रदेश की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी पार्टी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। नारायणगढ़ के छोटे से गांव में जन्मा हरियाणा सरकार का यह नायक बिहार व दिल्ली के चुनाव में तो सफल रहा ही है, अब पंजाब में भी लोकप्रियता के नए मुकाम छू रहा है।

मुख्यमंत्री के तौर पर मजबूती से आगे बढ़ रहे नायब

भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेशाध्यक्ष और सरकार में राज्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक हर भूमिका में स्वयं का साबित कर चुके नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अनूठी पहचान बना रहे हैं। आमजन सा दिखने वाला यह मुख्यमंत्री जब अपने जीवन के 56 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो प्रदेश की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी पार्टी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। नारायणगढ़ के छोटे से गांव में जन्मा हरियाणा सरकार का यह नायक बिहार व दिल्ली के चुनाव में सफल रहा ही है, अब पंजाब में लोकप्रियता के नए मुकाम छू रहा है। प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा निभाकर सबका भाई बन चुका यह राजनेता सत्ता के शिखर पर बैठ कर भी सबको अपना सा लगता है। अपने ठेठ हरियाणवी सरल, सौम्य अंदाज में आम जन के दिलों में लगातार जगह बना रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जन्मदिन है।

नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री तक के सफर पर नजर डाली जाए तो उनके परिवार की जड़ें कुरुक्षेत्र के गांव मंगोली जाटान से जुड़ी हुई हैं। बाद में उनका परिवार अंबाला के मिर्जापुर माजरा शिफ्ट हो गया। जहां भविष्य मे प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अंतिम छह माह में प्रदेश का नेतृत्व अपने हाथ में संभालने वाला बालक पैदा हुआ। 25 जनवरी 1970 को जन्में नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक ककहरा भाजपा की पाठशाला में ही सीखा। उन्होंने अंबाला में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर राजनीतिक पाठशाला में दाखिला लिया। इसके बाद वे किसान मोर्चा में महामंत्री बनें। गो संरक्षण में योगदान दिया। बाद में वे अंबाला में भाजपा के अध्यक्ष भी बनें। 2009 का विधानसभा चुनाव भी नायरायणगढ़ हलके से लड़ा लेकिन पहला चुनाव वे हार गए। इसके बाद भी उन्होंने सक्रियता जारी रखी। उन्होंने अगला चुनाव 2014 में भी नारायणगढ़ से लड़ा और 24 हजार से अधिक वोटों से विजयी हुए। पहली ही बार में विधायक बनते ही उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया। इसके बावजूद वे पार्टी संगठन के कार्यालयों से जुड़े रहे, प्रदेश व राष्ट्रीय संगठन के लिए काम करते रहे। इसके बाद उनका राज्यमंत्री का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था कि उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा से 2019 का भाजपा का टिकट थमा दिया गया और वह सांसद चुने गए। बतौर सांसद भी उन्होंने अपने कार्य से अमिट छाप छोड़ी और वे कैथल व कुरुक्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने आमजन के बीच रहकर उनके कष्ट दूर करवाए। बतौर सांसद उनका कार्यकाल शानदार रहा था यही कारण है कि भाजपा आला कमान उनके कार्य की इतना मुरीद हो गई कि उन्हें हरियाणा भाजपा के संगठन की कमान सौंप दी गई। बतौर सांसद उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनें भी कुछ ही माह हुए थे कि भाजपा आलाकमान व विधायकों के समर्थन से प्रदेश मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने करनाल से विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा और जीता। महज छह माह में उन्होंने हरियाणा में बतौर सीएम ऐसी छाप छोड़ी कि हरियाणा की जनता ने ऐसे माहौल में उन्हें हरियाणा की बागडोर सौंप दी, जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की 70 सीटें आने की बात कही जा रही थी लेकिन यह नायब सिंह सैनी ही थे जो लगातार कह रहे थे कि भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है।

प्रदेश की जनता को उन पर विश्वास ही था कि 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने स्पष्ट बहुमत से भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंप दी। उन्होंने सीएम बनते ही प्रदेश में सीएम आवास के दरवाजे आमजन के लिए खोल दिए। अपनी पहली कलम से हरियाणा के किसानों को फसल खराब होने का 88 करोड़ मुआवजा देने की शुरूआत कर मुख्यमंत्री ने आज तक ऐसे अनेकों फैसले लिए हैं, जो आने वाले समय में नजीर बनकर याद किए जाएंगे। प्रदेश में दौरे के बीच में अलाव सेंकते, सड़क पर स्वागत के लिए खड़े और गांवों में पेड़ की छांव में बैठे बुजुर्गों व आम लोगों के बीच जाकर उनका हाल-चाल जानना और उनकी समस्याएं सुनना मुख्यमंत्री को आम जन मानस के बीच खड़ा करता है और हरियाणा का आम जन मानस यह महसूस करता है कि वे हमारे राजा नहीं बल्कि हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं। जो आम आदमी के दुख-दर्द को बखूबी समझते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कैंसर के मरीजों के लिए मदद सहित 54 दुलर्भ बीमारियों के इलाज में सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया, इसके बाद एक लाख अस्सी हजार तक की आय वाले परिवारों के 84 लाख लोगों को एक हजार किलोमीटर तक निःशुल्क बस यात्रा का

जन्मदिन विशेष
नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री हरियाणा

तोहफा नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जनता को दिया। उन्होंने 50 हजार सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष द्वारा चयन के बावजूद ज्वाइनिंग पर सवाल उठाने पर नायब सिंह सैनी ने विश्वास दिलवाया था कि वे शपथ बाद में लेंगे और युवाओं को ज्वाइनिंग पहले करवाएंगे। चुनाव परिणाम आने पर युवाओं से किया वादा पूरा किया। उनकी अगुवाई में अनुसूचित जाति के ए व बी के विभाजन को मंजूरी दी गई। 7500 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को सौ-सौ गज के प्लाटों पर कब्जा दिलवाया। आमजन की शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए उन्होंने समाधान पोर्टल शुरू करवाया। हर सोमवार व वीरवार को उपमंडल व जिलास्तर पर अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठकर आमजन की शिकायतें सुनते हैं। स्वयं सीएम नायब सिंह सैनी कई बार इन शिविर में भाग लेकर आमजन की शिकायत सुन चुके हैं। उन्होंने पिछले साल सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत अगस्त माह तक हो जानी चाहिए। नायब सिंह सैनी ही थे, जिन्होंने भवन निर्माण मजदूरों के लिए रुके हुए लाभ को तुरंत जारी करवा दिया। उनके नेतृत्व में बाढ़ प्रबंधन की रणनीति तैयार हुई। सीएम की जमीनी स्तर पर समस्याओं की पकड़ इतनी गहरी है कि उन्होंने दाखिले के समय ही अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के आदेश जारी किए। वहीं निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से 121 एचसीएस एलाइड सर्विसेज के अधिकारियों का परिणाम जारी हुआ। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को 100 से अधिक योगशालाएं दीं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ग्रुप सी की नौकरियों में पात्र खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत अलग से कोटा देने का फैसला लिया। उन्होंने हिसार हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का ऐतिहासिक फैसला लिया। जिसके लिए 544 करोड़ रुपये की राशि से शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। पिछड़ा वर्ग को लाभ देते हुए उन्होंने क्रीमीलेयर की आय सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी। स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों की पेंशन को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दी। आपातकाल में सेनानियों व हिंदी आंदोलन के सेनानियों की पेंशन दस हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दी। उन्होंने जून 2024 में ही प्रदेश में जल वितरण व्यवस्था के लिए एक हजार करोड़ की भारी भरकम राशि की मंजूरी दी। तीन लाख रुपये तक निःशुल्क किडनी व लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने इसी अवधि जून 2024 में एचकेआरएन के कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की, इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका, नगर परिषद के सफाई कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 17 हजार करने व ग्रामीण सफाई कर्मियों का मानदेय 16 हजार करके विशेष तोहफा देने का काम किया। कई साल से हरियाणा में सरपंचों के लिए मुद्दा बनी समस्या का समाधान करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बिना टेंडर लगाए कार्य करवाने की सीमा 21 लाख तक तय करने व सरपंचों को हरियाणा में टीए व डीए देने का पहली बार ऐतिहासिक फैसला लागू किया। वन मित्रों को भी बीस रुपये प्रति पेड़ देने का फैसला लिया। वहीं अग्निवीर योजना में काम करके आने वाले युवाओं को रोजगार की गारंटी देने की पहल करते हुए कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फोरेस्ट गार्ड व जेल वार्डन व एसपीओ की सीधी भर्ती में पहले दस प्रतिशत आरक्षण बाद में पुलिस भर्ती में कोटा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत देने वाला हरियाणा का पहला राज्य बनाने का काम किया। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला लेकर किसानों को बड़ी राहत प्रदान की। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछड़ा वर्ग में बी श्रेणी को भी आरक्षण देने का बड़ा फैसला लागू किया। इसके साथ ही गो संरक्षण के लिए प्रतिदिन चार रुपये प्रति गाय के हिसाब से दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर पांच गुणा कर दिया। अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी को पक्का करने का आाम किया। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का फैसला लागू किया। महिला उत्थान के लिए उन्होंने ड्रोन दीदी योजना के अलावा सक्षम युवा व आईटी सक्षम युवा योजना को लागू किया।महापुरुषों व गुरुओं की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। वीर बाल दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को विभाजित करने की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी देकर एससी एवं डीएससी को मंजूरी दी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव निष्पक्षता से संपन्न करवाया। कर्मचारियों को पदोन्नति एवं एसीपी स्केल के लाभ देने की मंजूरी दी गई। स्कूलों में योग सहायक नियुक्त करवाए। लाडो लक्ष्मी योजना को प्रदेश में लागू कर महिलाओं को मजबूत किया। मुख्यमंत्री ने पंजाब में बाढ़ आने पर तुरंत मदद पहुंचाई। मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को लगातार सौगातें देने के काम में लगे हुए है। इसके साथ वह अन्य प्रदेशों में भी पार्टी के लिए प्रचार करने गए। न केवल दिल्ली बल्कि महाराष्ट्र, बिहार चुनाव में नायब सिंह सैनी ने जहां भी प्रचार किया, वहां पार्टी विजयी हुई। अब पंजाब में उनकी सक्रियता से भाजपा को काफी उम्मीदें है। आलाकमान की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।

जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए विश्व बैंक देगा 5700 करोड़

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में विश्व बैंक द्वारा लगभग तीन दशकों के उपरांत हरियाणा प्रदेश को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के अंतर्गत 5,700 करोड़ के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग (ऋण) को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चण्डीगढ में जल संरक्षित हरियाणा कार्यक्रम को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि छह वर्षों के दौरान वर्ष 2026 से 2032 की अवधि में चरणबद्ध रूप से वितरित की जाएगी। इस राशि का

■ प्रोजेक्ट के पूरा होने से सभी नहरों का नेटवर्क हो जाएगा पक्का

उपयोग नहरी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के लिए किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 1,570 नहरों में से 892 नहरों का पिछले 20 वर्षों में पुनर्वास किया जा चुका है तथा अगले पाँच वर्षों में शेष 678 नहरों का पुनर्वास किया जाना प्रस्तावित है।

इसमें विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग 2,325 करोड़ की लागत से 115 नहरें, राज्य बजट से 2,230 करोड़ की लागत से 284 नहरें तथा नाबार्ड द्वारा 2,880 करोड़ की लागत से 279 नहरों का पुनर्वास किया जाना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने 109 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे

युवा विकसित भारत का आधार, 2047 के लक्ष्य को करेंगे साकार : मनोहर लाल

पंचकूला। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की 50वीं वाहिनी, सेक्टर-26, पंचकूला में रोजगार मेले की श्रृंखला के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री मनोहर लाल रहे। कार्यक्रम में पवन कुमार नेगी, उप महानिदेशक, क्षेत्रीय मुख्यालय (शिमला) भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसबीआई, गेल सहित अन्य केंद्रीय संस्थानों में चयनित 109 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मनोहर लाल ने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं की हर प्रकार से चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण युवाओं की शिक्षा, उनकी स्किलिंग, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि युवा ही विकसित भारत का आधार है ओर 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे है।

हरियाणा लोक भवन में मना उत्तर प्रदेश दिवस

चंडीगढ़। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने शनिवार को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं, और राज्य को भारत की सभ्यता, आध्यात्मिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की आत्मा बताया। प्रथम महिला मित्रा घोष, फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर, राज्यपाल के सचिव डीके बेहेरा, आईएएस, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे।हरियाणा लोक भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह को संबोधित करते हुए, माननीय राज्यपाल प्रो. घोष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक

और ऐतिहासिक विरासत का एक शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह राज्य अयोध्या, मथुरा और काशी का घर है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना के तीन शाश्वत स्तंभ हैं। अयोध्या में राम मंदिर आज आस्था, एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक शक्तिशाली प्रतीक है।

करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की दी शिकायत

पलवल चुनाव : हाईकोर्ट में सबूत के तौर पर सौंपी पेन ड्राइव गायब

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम के पलवल विधानसभा सीट चुनाव को चुनौती देने वाली हाई प्रोफाइल चुनावी याचिका में बेहद गंभीर और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिकार्ड से एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक सबूत यानी पेन ड्राइव के गायब होने से न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह पेन ड्राइव चुनाव याचिका करन सिंह दलाल बनाम गौरव गौतम मामले में एनेक्सचर पी-4 के रूप में दाखिल की गई थी, जिसमें चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और स्क्रीनशाट सुरक्षित थे। करन सिंह दलाल ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायत दर्ज कराई है कि 21 जनवरी 2026 को उन्हें चुनाव शाखा की ओर से सूचित किया गया कि अदालत की फाइल से पेन ड्राइव गायब है। उनके वकील को दोपहर करीब 12.06 बजे फोन कर बताया गया कि कागजी बंडल के पृष्ठ संख्या 72 पर प्लास्टिक पाउच में लगी पेन ड्राइव को किसी ने निकाल लिया है ।शिकायत में बताया गया है कि यह पेन ड्राइव सीरियल नंबर बीएम2409003429 जेड की थी, जिसमें वे सभी वीडियो और डिजिटल सबूत थे, जिनके आधार पर राज्य मंत्री गौरव गौतम पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है। हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट के 28 नवंबर 2025 के आदेश में भी इन्हीं वीडियो सबूतों का उल्लेख किया गया था।

सब-इंस्पेक्टर भर्ती विवाद खत्म, याचिका खारिज

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े एक विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चयन प्रक्रिया की उत्तर-कुंजी को चुनौती दी गई थी। जस्टिस जगमोहन बंसल की एकलपीठ ने स्पष्ट कहा कि जब चयन आयोग ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर उत्तर-कुंजी तय की है और उसमें कोई स्पष्ट त्रुटि सिद्ध नहीं हुई है, तो अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस मामले में याचिकाकर्ता अमित ने विज्ञापन संख्या 3/2021 के तहत हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तीन प्रश्नों की उत्तर-कुंजी पर सवाल उठाए थे। परीक्षा प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक माप और दस्तावेजों की जांच शामिल थी और मेरिट लिखित अंकों, अतिरिक्त योग्यता तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर तैयार की जानी थी ।अमित ने 26 सितंबर 2021 को हुई लिखित परीक्षा में भाग लिया था।

■ गलत सामाजिक-आर्थिक लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को नहीं मिली कोई राहत

डॉ. अनिल के मार्गदर्शन में विवि के विद्यार्थियों ने किया कमाल

एमडीयू ने सुपरकैपेसिटर का एक प्रोटोटाइप तैयार करके हासिल की बड़ी उपलब्धि

ई-परफॉरमेंस सुपरकैपेसिटर से हाइब्रिड वाहनों और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा क्रांतिकारी बदलाव

रोहित डागर ▶▶ रोहतक

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) रोहतक का भौतिकी विभाग ने ऊर्जा भंडारण की दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की। विभाग के एप्लाइड रिसर्च (अनुप्रयुक्त अनुसंधान) विंग में सुपरकैपेसिटर पर चल रहे अत्याधुनिक शोध ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं।

डॉ. अनिल ओहल्याण के कुशल मार्गदर्शन में लतीशा गाबा, ईशु खत्री व प्रिया सिवाच चार शोधार्थी निरंतर ऐसी तकनीक विकसित करने में जुटे हैं, जो न केवल ऊर्जा को तेजी से स्टोर करेगी बल्कि बैटरी के मुकाबले कहीं अधिक टिकाऊ भी होगी। डॉ. अनिल ने बताया कि सुपरकैपेसिटर का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। यह प्रोटोटाइप लैब के लिए बनाया गया है। भविष्य में इसका प्रयोग व्यावसायिक रूप में भी होगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम : डॉ. अनिल

डॉ. अनिल ओहलान और उनकी टीम की ओर से तैयार किए गए सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स का परीक्षण 'पोटेंशियोस्टेट' नामक आधुनिक उपकरण पर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस शोध के सफल परिणाम आने वाले समय में हाइब्रिड वाहनों के लिए वरदान साबित होंगे। वाहनों को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक 'पावर बर्स्ट' और ब्रेक लगाने पर पैदा होने वाली ऊर्जा को वापस स्टोर करने (रिजेनरेशन) में यह तकनीक सबसे कारगर है। इसके अलावा, ग्रिड के स्थिरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर/विंड) के भंडारण, और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे कि सेंसर, स्मार्ट वॉच और रोबोटिक्स में इसका व्यापक उपयोग देखा जा रहा है। वर्तमान में दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्ट गैजेट्स की ओर बढ़ रही है। ऐसे में डॉ. ओहलान और उनके शोधार्थियों द्वारा तैयार किए गए ये उच्च प्रदर्शन वाले सुपरकैपेसिटर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं।

लतीशा गाबा

ईशु खत्री

प्रिया सिवाच

आगे यह शोध चल रहा

डॉ. अनिल ने बताया कि सामान्य बैटरी चार्ज में होने में समय लेती है व धीरे-धीरे डिस्चार्ज होती है। वहीं, सुपर कैपेसिटर चार्ज तो जल्दी हो जाता है, लेकिन डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। इस पर यह काम किया जा रहा सुपरकैपेसिटर भी बैटरी की तरह डिस्चार्ज धीरे-धीरे हो। हम कोशिश कर रहे है कि यह इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी की जगह ले। बैटरी में घनत्व ज्यादा होता व पावर कम होती है। कैपेसिटर में ऊर्जा कम होती है व पावर बहुत ज्यादा होती है। सुपरकैपेसिटर हम ऐसा बनाना चाहते है इसमें ऊर्जा भी ज्यादा हो और पावर भी ज्यादा हो। दोनों चीजे बढ़नी चाहिए।

ऐसे काम करता है सुपरकैपेसिटर

सुपरकैपेसिटर एक आधुनिक ऊर्जा भंडारण उपकरण है, जो पारंपरिक बैट्री और साधारण

कैपेसिटर के बीच की कड़ी का काम करता है। जहां साधारण बैटरियां रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा स्टोर करती हैं, वहीं सुपरकैपेसिटर स्थिरवैद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की गति है, जो बिजली की रफ्तार से काम करती है। इसे कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि सामान्य बैट्रियां कुछ सालों में खराब हो जाती हैं। यह अत्यधिक गर्म और ठंडे, दोनों तरह के वातावरण में समान दक्षता से कार्य करने में सक्षम है। इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है, जो इसे कम समय में भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करने की शक्ति प्रदान करता है। शोधकेमिकल इंजीनियरिंग जर्नल 2025, कोलाइड और इंटरफेस साइंस में एडवांस 2025, जर्नल ऑफ़ मैटेरियल्स केमिस्ट्री 2024, जर्नल ऑफ एनर्जी स्टोरेज सहित अन्य में प्रकाशित हो चुका है।

एचसीएमएस की चुनावी जंग पर फैसला आज, बैलेट पेपर से होगा मतदान

योगेंद्र शर्मा ▶▶ चंडीगढ़

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएस) के अध्यक्ष और बाकी पदों की कुर्सी का चुनाव रविवार को मतदान के जरिये होगा। देर शाम को चुनाव अधिकारी डा.संदीप ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर के जरिये यह चुनाव होगा और तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बाकी पहले की तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो इसकी अपील करेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का पहरा भी रहेगा। रविवार को सुबह दस बजे से पांच बजे तक वोटिंग का समय रखा गया है। पूरे प्रदेश से आकर प्रतिनिधि मतदान करेंगे। दूसरी, तरफ एक वोटर छह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करेगा। प्रदेशाअध्यक्ष की कुर्सी के साथ साथ में बाकी पदों के लिए भी रविवार को पानीपत समालखा में होगा। प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर अच्छा खासा संघर्ष इस बार दिखाई दे रहा है। यहां पर बता दें कि सबसे पहले जिलों में कॉलेजियम प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, इसके बाद वे अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करते हैं। अब से पहले तीन-तीन साल के लिए दो बार प्रदेशाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके डाक्टर राजेश खयालिया इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं, उनका कहना है कि नए साथियों को काम करने का मौका देना चाहिए। हालांकि वे उनके साथ में महासचिव पद की जिम्मेदारी निभा रहे अनिल यादव को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतार चुके है। कुल मिलाकर 25 की देर शाम तक अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला वोटर लिख देंगे। उल्लेखनीय हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के तीन पैनल हैं। छह की छह पोस्ट के लिए तीन-तीन उम्मीदवार भाग्य आजमाने के लिए मैदान में हैं। वैसे राज्यभर में लगभग 29 सौ चिकित्सक इसके सदस्य हैं। प्रदेशाअध्यक्ष पद के अलावा वरिष्ठ उपप्रधान, उपप्रधान सचिव महा सचिव और पदाधिकारी हैं। इसमें 136 कॉलेजियम सदस्य राज्य इकाई का चुनाव करेंगे जिसमें तीन पैनल मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र सैनी, अनीश चहल और अनिल यादव के नाम चल रहे हैं। बाकी पदों के लिए भी तीन तीन उम्मीदवार मैदान में हैं।

■ चुनाव अधिकारी डॉक्टर संदीप करनाल ने गठित की टीम, समालखा जुटेंगे प्रदेशभर के चिकित्सक

रोहतक
रविवार 25 जनवरी 2026
माघ मास, शुक्ल पक्ष,
सप्तमी वर्ष : 29, अंक : 357
पृष्ठ : 16 मूल्य : 3.00

मौसम
अधि. 17.4
न्यून. 1.6

हरिभूमि

हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

09 भीषण गर्मी से जूझे टेनिस सितारे, सिनर, कीज पेगुला और अनिसिमोवा जीते, ओसाका बाहर

अमेरिकी वित्तमंत्री बोले- भारत ने रूस से घटाई तेल खरीद

ये अमेरिका की बड़ी जीत
टैरिफ में राहत देने की बन रही गुंजाइश

भारत पर लगा एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका

एजेंसी ▸▸ वाशिंगटन

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधा टैरिफ हटाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, इसलिए टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है। बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया और कहा कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ काफी असरदार रहा है और इसकी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद घट गई है। उन्होंने कहा कि टैरिफ अभी भी लागू हैं, लेकिन अब इन्हें हटाने का रास्ता निकल सकता है। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर दो बार टैरिफ लगाया था। पहली बार 1 अगस्त को व्यापार घाटे को लेकर 25% टैरिफ लगाया गया। इसके बाद 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने की वजह से एक बार और 25% टैरिफ लगाया गया।

अमेरिका ने 2025 में भारत पर दो बार टैरिफ लगाया
दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी

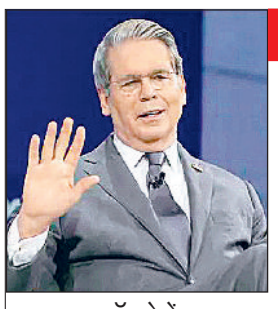
स्कॉट बेसेंट

बेसेंट ने कहा
- यूरोपीय देश भारत पर टैरिफ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वे भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते हैं
- यूरोप भारत से रिफाइंड तेल खरीदकर खुद ही रूस की मदद कर रहा

अमेरिका पुतिन पर बढ़ाना चाह रहा दबाव

अमेरिका, पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत समेत कई देशों से कह रहा है कि वे रूस से तेल खरीद बंद करें। भारत ने इस दबाव को गलत और अनुचित बताया है और कहा है कि उसकी एनर्जी पॉलिसी देश के हितों के हिसाब से तय होती है। पिछले हफ्ते दावोस में भी बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से कहा था कि ट्रम्प के 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने तेल की खरीद काफी कम कर दी थी और अब लगभग बंद कर दी है। भारत की कुछ निजी कंपनियों ने रूस से तेल इंपोर्ट कम किया है।

अब कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अब कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कनाडा को चीन के साथ व्यापार को लेकर सख्त चेतावनी दी है। ट्रम्प ने कहा कि अगर गवर्नर मार्क कार्नी (कनाडाई पीएम) ये सोचते हैं कि वे कनाडा को चीन का ऐसा रास्ता बना देंगे, जहां से चीन अपना सामान अमेरिका भेज सके, तो वे गलत हैं। ट्रम्प ने कहा कि चीन, कनाडा को पूरी तरह नुकसान पहुंचा देगा। चीन, कनाडा के कारोबार, समाज और जीवनशैली को खत्म कर देगा और देश को पूरी तरह निगल जाएगा।

भारत कई देशों से कर रहा ट्रेड डील

युवाओं के लिए नए अवसर खोल रहे व्यापार समझौते: पीएम मोदी

नई दिल्ली (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत देश के भीतर और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते कर रहा है। मोदी ने यह बात 18वें रोजगार मेले में कही जहां उन्होंने विभिन्न सरकारी नौकरियों के 61,000 नियुक्ति पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सौंपे। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेलों को संबोधित करते हुए कहा, ''भारत कई देशों के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते कर रहा है।

- प्रधानमंत्री ने 18वें रोजगार मेले में बांटे नियुक्ति पत्र
- 61000 युवाओं को विभागों में नौकरियां मिली

भारत में युवाओं की सबसे अधिक संख्या

मोदी ने कहा कि दुनिया में युवाओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है और उनकी सरकार देश के भीतर और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान में कहा गया कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। बयान में कहा गया कि इसकी शुरुआत के बाद से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

बारिश और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से 8 डिग्री तक गिरा पारा

शीतलहर से कांपा हरियाणा, फसलों पर जमा पाला, 14 जिलों में आज घना कोहरा

हिसार 1.6 डिग्री के साथ रहा सबसे ठंडा
नारनौल में ठंड लगने से मजदूर की मौत

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा में एक दिन पहले हुई बारिश के बाद शनिवार को ठंड बढ़ गई। पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। हिसार 1.6 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। सिरसा व कई अन्य क्षेत्रों में सुबह पाला जमा मिला। हालांकि मौसम फिलहाल साफ है, धूप भी खिली है, लेकिन शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसत तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री नीचे पहुंच गया है। साथ ही रविवार को 14 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। नारनौल में ठंड के कारण 43 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई। नन्हें यूपी के अमरोहा से गांव बाछोद में मजदूरी करने आया था। सुबह उसका शव हवाई पट्टी मार्ग पर पड़ा मिला।

आईसीसी की डेडलाइन पूरी, बीसीबी का भारत में खेलने से इनकार

बांग्लादेश टी-20 वर्ल्डकप से बाहर, स्कॉटलैंड खेलेगा

पाकिस्तान भी बोला, हमारा खेलना अभी तय नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो गया है, वहीं स्कॉटलैंड को एंट्री मिल गई है। आईसीसी ने स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार रहने को कहा है। आईसीसी ने शुक्रवार शाम को बांग्लादेशी बोर्ड को इसकी जानकारी दी है। उधर, आईसीसी के फैसले से पाकिस्तान झल्ला गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा कि अब पाकिस्तान के खेलने के बारे में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के इस्लामाबाद आने पर ही अंतिम निर्णय होगा। भारत में मैच खेलने के आईसीसी के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी (डीआरसी) में जो अपील की थी, उस पर सुनवाई की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह मामला समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

ऐसे बढ़ा पूरा विवाद
- बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्याओं के विरोध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवा दिया। बीसीबी ने इसका विरोध किया।
- मुस्तफिजुर को बाहर किए जाने को बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा बना दिया। फिर यूनुस सरकार ने अपने देश में आईपीएल प्रसारण पर बैन लगा दिया। इसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने भारत में वर्ल्ड कप न खेलने की मांग की, जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया।

खबर संक्षेप

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ इजाफा

नई दिल्ली। डॉलर में उतार-चढ़ाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, फॉरेन करेंसी और सोने के भंडार में आई मजबूती की वजह से 16 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 14.17 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद कुल भंडार बढ़कर 701.36 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जो 17 अक्टूबर 2025 के बाद का सबसे ऊंचा लेवल है।

40 से अधिक देशों में होगा एसआईआर, बनी सहमति

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने अपने यहां मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए तरीका अपनाने पर बल दिया है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों और 27 देशों के मिशन प्रमुख ने मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की।

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग

27 जनवरी को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल, 4 दिन सेवाएं रहेंगी बाधित

नई दिल्ली (एजेंसी)। बैंक कर्मचारी संगठनों ने पांच दिन के कार्य सप्ताह की अपनी लंबे समय से अनसुनी मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर यह हड़ताल होती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज लगातार तीन दिनों तक बाधित रहेंगे, क्योंकि 25 और 26 जनवरी को पहले से ही छुट्टियां हैं। बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को बता दिया है कि अगर हड़ताल होती है, तो बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के नौ संगठनों के शीर्ष निकाय- यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने एक बयान में कहा, इस समय बैंक कर्मचारियों को रविवार के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है। सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने पर मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और यूएफबीयू के बीच सहमति बनी थी।

25 और 26 जनवरी को सरकारी छुट्टी, ग्राहकों को होगी परेशानी

मां-बेटी की मौत, दूसरी बच्ची गंभीर

बेटा नहीं होने से परेशान मां 2 बेटियों संग ट्रेन के आगे कूदी

हांसी (हरिभूमि न्यूज)। मां अपनी दो बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। सूत्रों के मुताबिक, महिला को शादी के बाद 4 बेटियां हुईं। वह बेटा न होने से परेशान चल रही थी। पुलिस पता लगा रही है कि महिला ट्रेन की चपेट में आई है या उसने जानबूझकर अपनी बच्चियों के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगाई है। घटना रामायण और मय्यड़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई। हादसे में मां और एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को हांसी सिविल अस्पताल से हिसार रेफर कर दिया गया है। महिला की पहचान भगाना गांव की निर्मला (35) के तौर पर हुई। उसकी बेटी निकिता (6) की भी मौत हुई है। साढ़े 3 साल की प्रीति के होंठ और चेहरे पर चोट आई है। निर्मला का पति नरेंद्र खेतीबाड़ी करता है। निर्मला घर से मां को मिलने की बात कहकर निकली थी।

महिला भगाना गांव की, रामायण और मय्यड़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई घटना

फर्जी हस्ताक्षरों से बनाए फॉर्म-75, रिटायर्ड कर्मी की जमीन पर लगा 'लाल स्याही' का नोट

पानीपत में आबकारी विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला

पानीपत (हरिभूमि न्यूज)। जिले में आबकारी विभाग के अधिकारियों और एक शराब ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी धन की हेराफेरी और गंभीर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। मतलौडा तहसील के गांव नारा निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक पानीपत को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनकी और उनके भतीजे के फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग कर करोड़ों रुपये के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी समेत आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ऐसे हुआ खुलासा

पीड़ित चांद सिंह के अनुसार जब वे वर्ष 2024 में जमीन की जमाबंदी निकलवाने तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनकी जमीन की जमाबंदी पर 'लाल स्याही' का नोट लगा हुआ है। जांच करने पर पता चला कि दोषी कुलबीर (निवासी गांव जोशी) ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वर्ष 2020-2021 के लिए शराब के ठेके की सिक्योरिटी से संबंधित फर्जी फॉर्म-75 तैयार किए थे। शिकायत में बताया गया है कि दोषी कुलबीर ने वर्ष 2017 में अपने ठेके के लिए विभाग में जमा करवाई गई वर्ष 2014-2015 की पुरानी जमाबंदी का दुरुपयोग किया।

चंडीगढ़ में मिलेंगे दोनों राज्यों के सीएम

एसवाईएल पर हरियाणा और पंजाब के बीच फिर होगी बैठक

चंडीगढ़। सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर एक बार फिर हरियाणा और पंजाब मीटिंग करने जा रहे हैं। ये मीटिंग इस बार दिल्ली में नहीं चंडीगढ़ में होगी। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में केंद्र का कोई मंत्री शामिल नहीं होगा। बैठक चंडीगढ़ में 27 जनवरी को हरियाणा निवास में होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सहित दोनों सरकारों के सीनियर अफसर भी शामिल होंगे। इससे पहले भी एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने के लिए जुलाई, अगस्त और नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठकें हो चुकी हैं। इन दोनों बैठकों में कोई हल निकला था, जिसके बाद अब इस साल की एसवाईएल को लेकर ये पहली बैठक बुलाई गई है।

केंद्र का कोई मंत्री नहीं होगा शामिल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस विवाद सुलझाने के लिए पिछले साल हो चुकी कई बैठकें

पहलगाम जैसी घटना को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जा सकता

कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का विरोध नहीं किया, केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर थी असहमति : शशि थरूर

राजनीतिक दलों में मतभेद हो सकते हैं

राष्ट्रीय हित में सिर्फ भारत को ही जीतना चाहिए

एजेंसी ▸▸ तिरुवनंतपुरम

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का कभी भी विरोध नहीं किया। एकमात्र मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर था, जिस पर सिद्धांत के आधार पर मेरा स्टैंड अलग था। थरूर ने कहा- इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा। पहलगाम की घटना के बाद, मैंने खुद कहा था कि ऐसी घटना को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता और इसका जवाब देना जरूरी है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने यह बातें शनिवार को कोझिकोड में आयोजित केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कहीं। वह वहां दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

सुरक्षा के मामले में देश सबसे पहले
- ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर कड़े रुख का कोई पछतावा नहीं है। भारत को विकास पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ लंबे संघर्ष में नहीं उलझना चाहिए।
- किसी भी कार्रवाई को आतंकवादी शिविरों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। मुझे हैरानी हुई कि भारत सरकार ने वही किया, जैसा मैंने सुझाया था।
- जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अगर भारत मर जाता है, तो कौन जीवित रहेगा? उनका कहना था कि जब देश की सुरक्षा और दुनिया में उनकी स्थिति का सवाल हो, तो भारत सबसे पहले आता है।
- राजनीतिक दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में सिर्फ भारत को ही जीतना चाहिए।
- पार्टी मीटिंग में नहीं जाने पर कहा- दिल्ली से कोझिकोड वापस आना आसान नहीं।

मीटिंग में नहीं आने पर दिया जवाब

शशि थरूर ने पार्टी मीटिंग में नहीं जाने पर मीडिया से कहा, 'मैं जो कहना चाहता था, वह मैंने पार्टी लीडरशिप को बता दिया है। यह सही नहीं है कि मैं इस बारे में पब्लिक में बात करूं।' उन्होंने कहा- मीडिया कई बातें कह सकता है, कुछ सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं। मैंने पहले ही पार्टी लीडरशिप को बता दिया था कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस

सीबीएसई के सभी स्कूलों में काउंसलर रखना अनिवार्य

नई दिल्ली (एजेंसी) बढ़ते पढ़ाई के दबाव और करियर को लेकर कन्फ्यूजन के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने छात्रों के हित में अहम फैसला सुनाया है। बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और करियर काउंसलर की नियुक्ति जरूरी कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद सीबीएसई ने अपने नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब हर सीबीएसई स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य और करियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। यह याचिका, कोटा के वकील सुजीत स्वामी और कुछ मनोविज्ञान विशेषज्ञों की ओर से जुलाई 2025 में दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि पढ़ाई के दबाव की वजह से छात्रों में तनाव बढ़ रहा है और उन्हें सही करियर मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा।

शहीद सुधीर का पैतृक गांव शेरपुर में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

सात वर्षीय बेटे अयांश ने दी पिता को मुखाग्नि, डोडा में सड़क हादसे में शहीद हो गए थे

शहीद जवान की अंतिम यात्रा में हजारों लोग पहुंचे अमर रहे के नारे लगे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ यमुनानगर

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए गांव शेरपुर निवासी सुधीर नरवाल का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव शेरपुर पहुंचा। जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुधीर के सात वर्षीय बेटे अयांश ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भी शहीद को पुष्प भेंट किया।

यमुनानगर। गांव शेरपुर में तिरंगे में लिपटे शहीद सुधीर नरवाल के शव को सैन्य सम्मान के साथ सलामी देते सेना के जवान। फोटो: हरिभूमि

ग्रामीणों ने शहीद अमर रहे के नारे लगाए

इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद अमर रहे के नारे लगाए। पार्थिव देह सेना के काफिले के साथ गांव शेरपुर पहुंची। बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। तिरंगे में लिपटा शव देख शहीद सुधीर की मां के साथ अन्य परिजनों के भी आंसू छलक आए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शहीद अमर रखे के नारे लगाए। शहीद सुधीर के सात वर्षीय बेटे अयांश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी।

शहीद मोहित सैनिक सम्मान के साथ पंच तत्व में विलीन, नमन करने के लिए उमड़ा जनसैलाब

शहीद के छोटे भाई जितेंद्र ने मोहित के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ झज्जर

शहीद सैनिक मोहित के अंतिम संस्कार में उनके पैतृक गांव में गिजाडोध में किया गया। सैकड़ों की संख्या में युवा व ग्रामीणों ने भारत माता की जय, शहीद मोहित अमर रहे के नारे लगाए। शहीद के छोटे भाई जितेंद्र ने मोहित के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने हवा में फायर कर सलामी दी, मातमी धुन बजाकर शहीद के सम्मान में शस्त्र उल्टे किए। मोहित अमर रहे और भारत माता के जयकारों से पूरा गमगीन माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि ,प्रशासन की ओर से एसडीएम अंकित कुमार चौकसे ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नमन किया।

झज्जर। शहीद मोहित को मुखाग्नि देते हुए छोटा भाई जितेंद्र। फोटो: हरिभूमि

लोगों ने अपने बेटे को नम आंखों से दी विदाई

शहीद मोहित के पैतृक गांव गिजाड़ौद के अलावा आसपास क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में युवाओं की टोलियां बाइक और ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर अपने लाडले के पार्थिव शरीर लाने के लिए झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग स्थित पुल के नीचे एकत्रित हुए। जैसे ही सेना की गाड़ी शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंची तो युवाओं ने भारत माता की जय, शहीद मोहित अमर रहे के नारे लगाए।

खबर संक्षेप

पटाका फोड़ने वाले साइलेंसर पकड़े, दो लाख का जुर्माना

सोनीपत। सोनीपत में यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। तेज आवाज वाले साइलेंसर, बिना नंबर प्लेट या संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान छह बुलेट मोटरसाइकिलें और दो कारें इम्पाउंड की गईं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कुल 1 लाख 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दो बुलेटबाइक इम्पाउंड की गईं। इन मामलों में कुल चालीस हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

रोडवेज बस में यात्री से बदसलूकी

टोहाना। टोहाना से रतिया-फतेहाबाद रूट पर हरियाणा रोडवेज की बस में एक यात्री के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। यात्री ने बस कंडक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सैनी, परिवहन मंत्री अनिल विज को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है।

11 करोड़ की नशीली गोलियों के साथ तस्कर पकड़ा

डबवाली। सीआईए डबवाली ने प्रतिबंधित नशीली गोलियों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 11 करोड़ रुपए की करीब 2.95 लाख प्रतिबंधित गोलियों की तस्करी के मामले में दो मुख्य सप्लायरों को अमृतसर व बठिंडा पंजाब से काबू किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए खुईयां मलकाना टोल प्लाजा से कार को रुकवाकर का चालक सहित कार की तलाशी ली गई तो कार में 6 गत्ते के कार्टून में 590 डिब्बे जिनमें से 2 लाख 95 हजार प्रतिबंधित नशीली गोलियां (ट्रामाडोल) मिली।

छात्रों के लिए अब जापान में भी रोजगार के अवसर

हिसार। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अब जापान में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय ने जापानी शिक्षण संस्थानों के साथ आपसी सहयोग की संभावनाओं को तलाशा है। गुजवि शीघ्र ही जापानी शिक्षण संस्थानों के साथ कई महत्वपूर्ण एमओयू करेगा। गुजवि में विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिलेगे।

बाइक पर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

पानीपत में ट्रांसपोर्टर के सिर-पेट में गोलियां मारीं

यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रांसपोर्टर पर हमला क्यों और किसने किया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ पानीपत

पानीपत में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर को गोली मार दी। हमले में ट्रांसपोर्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल ट्रांसपोर्टर को अस्पताल पहुंचाया। ट्रांसपोर्टर के सिर में एक और पेट में 2 गोलियां लगी हैं। टीएनआर ट्रांसपोर्ट के संचालक चालीस वर्षीय सी. सुब्रमण्यम पिछले कई सालों से पानीपत में ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे है और वे दक्षिण भारतीय राज्यों से माल का पानीपत में आवागमन करवाते है। उनकी ट्रांसपोर्ट का ऑफिस, गांव महराणा के रकबे में है। इधर, ट्रांसपोटर सुब्रमण्यम पर हमला करने के बाद तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दूसरी ओर, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मुख्यालय ने बीटी कर जिला भर में पुलिस को चौकस कर दिया। दूसरी ओर, पुलिस ने बताया कि ट्रांसपोटर सुब्रमण्यम पर जान लेवा हमले के केस की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को पकड लिया जाएगा।

पानीपत। अस्पताल में भर्ती ट्रांसपोर्टर का इलाज करते डॉक्टर।

बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा

घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले में सख्त नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम से सभी थानों और पीसीआर को अलर्ट कर दिया गया। बदमाशों को पकड़ने के लिए सीआईए की तीनों यूनिटों, थाना पुलिस और साइबर सेल को काम पर लगा दिया गया है। बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। -भूपेंद्र सिंह, एसपी पानीपत

कैफे में युवक की चाकू मारकर हत्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

उत्तर पूर्वी जिले के वेलकम थाना इलाके में शुक्रवार देर रात एक कैफे में घुसकर 24 वर्षीय युवक की गोली व चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान फैजान उर्फ फज्जी के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि पैसों को लेकर हुए विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड कर हत्या करने की बात कही। डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 10:28 बजे वेलकम थाने में फायरिंग की घटना के संबंध में पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौजपुर स्थित मिस्टर किंग लाउंज और कैफे पहुंच गई। मौके पर एक युवक घायल मिला। अस्पताल पहुंचाने पर जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बदला लेने के लिए की हत्या

हत्या के बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में आरोपी ने कहा कि इस हत्या के पीछे मेरे किसी भी दोस्त व परिवार का हाथ नहीं है। मुझे किसी ने सूचना दी थी कि फैजान कैफे पर बैठा हुआ है। इसके बाद मैंने उसकी हत्या की।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, राज्यों के अधिकार छीन रही है केंद्र सरकार

यूजीसी के ड्राफ्ट नियम में बदलाव संघीय ढांचे पर हमला : राव नरेंद्र

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ चंडीगढ़

प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के ड्राफ्ट नियमों 2025 में प्रस्तावित बदलावों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इन बदलावों को देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार देते हुए कहा कि इससे राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। राव नरेंद्र सिंह ने विस्तार से कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद, केंद्र सरकार यूजीसी के माध्यम से विश्वविद्यालयों पर एकतरफा और केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। नए ड्राफ्ट नियमों में राज्य सरकारों की भूमिका को काफी हद तक कमजोर किया गया है, जिससे राज्यों की शैक्षणिक स्वायत्तता समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने विशेष रूप से कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। प्रस्तावित नियमों के तहत कुलपतियों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों में केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा है। जबकि राज्यों को महज दर्शक की भूमिका में धकेलने की कोशिश की जा रही है।

राज्यों को दर्शक की भूमिका में धकेलने की की जा रही है कोशिश

एचपीएससी बच्चों के भविष्य के साथ कर रहा खिलवाड़

इनेलो नेता कर्ण ने एचपीएससी के बाहर धरने पर बैठे युवाओं से मुलाकात की

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ चंडीगढ़

इनेलो युवा इकाई राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण चौटाला ने एचपीएससी के खिलाफ धरने पर बैठे असिस्टेंट प्रोफेसर (इंग्लिश) को पंचकूला सेक्टर 5 में धरना स्थल पर जाकर इनेलो की ओर से समर्थन दिया। इनेलो प्रदेश प्रधान महासचिव गौरव संपत सिंह, युवा इकाई प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी और छात्र इकाई आइएसओ के प्रदेश अध्यक्ष साहिल दीप कसवां इस दौरान मौजूद रहे। कर्ण चौटाला ने कहा कि एचपीएससी बच्चों भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सभी नेट पास किए हैं, उनमें से बहुत सारे पीएचडी हैं और जीआरफ क्वालिफाइड हैं। चौटाला ने एचपीएससी चेयरमैन पर जमकर हमला बोला और कहा कि चेयरमैन उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लायक नहीं मान रहे हैं और उलटा जिन यूनिवर्सिटी में वे पढ़े हैं उन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का स्तर बेहद खराब था।

कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर 40 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

फतेहाबाद। सेवानिवृत्त अध्यापक से विदेश भेजने और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर करीब 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा, फतेहाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान राकेश कुमार पुत्र रघुनंदन लाल निवासी कोटकपुरा, जिला फरीदकोट, पंजाब के रूप में हुई है। आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी निरिक्षक सन्दीप ने बताया कि इस बारे पुलिस ने खेमराज निवासी जाखल की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया गया।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भा.न.स.स.देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **(1) गुरविंदर सिंह** पुत्र राम सिंह, **(2) सुप्रीत कौर** पत्नी गुरविंदर, निवासी गाँव-बेनका, थाना-भिकीविंड, तरनतारन, पंजाब, **(3) अवतार सिंह उर्फ शेको** पुत्र बसंत, **(4) कृष्ण उर्फ मुख्यार** पुत्र रणजीत सिंह निवासी सरहाली, तरनतारन, पंजाब, **(5) रविकांत भार्गव** पुत्र रमेश चंद निवासी मकान नंबर 827/30, विकास कॉलोनी, सोनीपत, हरियाणा ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14586/25 धारा 305(बी)/317(2)(4)/317(4)/111(3)/318(2)/336(3)/338/340(2)/61(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना रानी बाग, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है की किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **(1)गुरविंदर सिंह, (2)सुप्रीत कौर, (3) अवतार सिंह उर्फ शेको, (4)कृष्ण उर्फ मुख्तार, (5)रविकांत भार्गव** मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त **(1)गुरविंदर सिंह, (2)सुप्रीत कौर, (3)अवतार सिंह उर्फ शेको, (4)कृष्ण उर्फ मुख्तार, (5)रविकांत भार्गव** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा कि जाती है की उक्त अभियुक्त **(1)गुरविंदर सिंह, (2)सुप्रीत कौर, (3)अवतार सिंह उर्फ शेको, (4)कृष्ण उर्फ मुख्तार, (5)रविकांत भार्गव, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14586/25 धारा 305(बी)/317(2)(4)/317(4)/111(3)/318(2)/336(3)/338/340(2)/61(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना रानी बाग, दिल्ली** न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **25.02.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेश से
सुश्री अनुराधा जिंदल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उत्तर पश्चिम
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

DP/930/OD/2026

हांसी: कांग्रेस विधायक के कार्यक्रम में युवक की मौत

साउंड सिस्टम लगाते हुए करंट लगा

खरबला गांव में कर्पूरी ठाकुर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक को आना था

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हांसी

खरबला गांव में नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ के कार्यक्रम के लिए साउंड सिस्टम लगाते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खरबला गांव में होने वाले कर्पुरी ठाकुर जयंती समारोह के लिए साउंड सिस्टम लगा रहा था, इसी दौरान बिजली तार की चपेट में आने से उसे करंट लग गया। करंट लगने के बाद आस-पास के लोगों ने उसे उपचार के लिए हांसी के एक निजी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ को खरबला गांव में कर्पूरी ठाकुर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आना था सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। जहां परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

हांसी। अमिताभ को करंट लगने की सूचना पर निजी अस्पताल में मौजूद परिजन। फोटो: हरिभूमि

मृतक की पहचान जींद जिले के गांव लोन गांव निवासी 35 वर्षीय अमिताभ के रूप में हुई है। अमिताभ वर्तमान में अपनी ससुराल चारकुतुब के समीप किराए पर मकान लेकर परिवार के साथ रहता था और ऑटो रिक्शा चला कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था।

सिरसा की प्लाइवुड फैक्ट्री से ब्लैक की यूरिया पकड़ी, सील

बिना लाइसेंस के खरीदने का आरोप

एग्रीकल्चर खाद का गत्ता-प्लाई बनाने में इस्तेमाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिरसा

किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग ने सिरसा जिले के गांव मोरीवाला स्थित एक प्लाइवुड की फैक्ट्री से चालीस थैले यूरिया खाद बरामद की है। पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने मौके से बरामद यूरिया को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है इस यूरिया का फैक्ट्री में गत्ता व प्लाई बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी विजेंद्र पाल ने शनिवार को बताया कि सूचना मिली थी कि प्लाईवुड की फैक्ट्री में यूरिया खाद से गत्ता व प्लाईवुड बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री वाले यूरिया का

इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली यूरिया अलग ग्रेड की आती है, जिसका थैला 50 किलो का होता है। पुलिस को दी शिकायत में कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी विजेंद्र पाल व विषय विशेषज्ञ कोमल की संयुक्त टीम गांव मोरीवाला निवासी गुरप्रीत की शिकायत पर फैक्ट्री में जांच के लिए पहुंचे। फैक्ट्री में बने कमरे में चालीस थैले यूरिया खाद के मिले, जिसे सील कर दिया गया है। इस मामले में विभाग ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और पुलिस ने शिकायत पर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्जकर लिया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय
हरियाणा सरकार
प्लॉट नं. सी-3, एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 6, पंचकूला 134109
फोन नं. 0172-2996509, ई-मेल : pmfme.haryana@gmail.com
www.msme.haryana.gov.in

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय, हरियाणा (राज्य नोडल एजेंसी) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना के तहत जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) के वॉक-इन इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

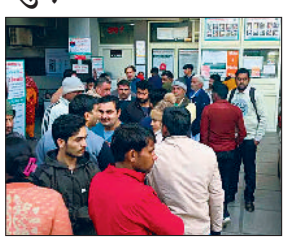

पोस्ट : जिला संसाधन व्यक्ति (पीएमएफएमई लाभार्थियों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों के लिए)। कृपया https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page पर विस्तृत योजना दिशानिर्देश देखें।

पात्रता : कोई भी उपयुक्त व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त सरकारी / बैंक अधिकारी, बीमा एजेंट, बैंक मित्र, परामर्श फर्म, व्यक्तिगत पेशेवर, आदि, जो परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और उचित परिश्रम में प्रासंगिक ज्ञान/अनुभव रखते हैं।

- खाद्य प्रसंस्करण, वित्त, या संबंधित क्षेत्रों में योग्यता वाले उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- डीआरपी को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें पुष्टि की गई हो कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

नोट: डीआरपी को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य-आधारित अनुबंध आधार पर पैनल में शामिल किया जाएगा और पारिश्रमिक भुगतान निम्नानुसार जारी किया जाएगा:

3. बैंक ऋण की मंजूरी के बाद रु. 10,000/-1
4. यूनिट/अतिरिक्त मशीनरी स्थापना और नीचे दिए गए दस्तावेज अपलोड करने के बाद रु. 10,000/-:
   ए. एफएसएसएआई पंजीकरण/लाइसेंस ।
   बी. उद्यम आधार।
   सी. जीएसटी (जहां लागू हो)।
   डी. वैब पोर्टल पर जियोलोकेशन के साथ फोटोग्राफ।

पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया:

- जिला स्तर कार्यालय या मुख्यालय, पंचकुला में वॉक-इन इंटरव्यू (वॉक-इन इंटरव्यू के लिए पता https://msme.haryana.gov.in/field-offices पर चेक किया जा सकता है)।

महानिदेशक
एमएसएमई, हरियाणा
पीआरडीएच-1066/11/57/2026/42315/88/6 दि. 22.01.026

प्यार में फंसाकर धर्म परिवर्तन, फिर निकाह

महिला ने थर्मामीटर तोड़कर निगला जहरीला पदार्थ, किया आत्महत्या का प्रयास

महिला बोली- पति ने टॉयलेट में बहाई भगवान की मूर्तियां

हरिभूमि न्यूज ▶▶ यमुनानगर

यमुनानगर में पहले से शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा कर निकाह किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद आरोपी व्यक्ति द्वारा महिला को परेशान किया जाने लगा और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। जिससे परेशान होकर महिला ने थर्मामीटर तोड़कर उसमें से निकला जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गंभीर हालत में महिला का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने महिला के बयान करवाकर आरोपी व्यक्ति व उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के तीर्थ नगर निवासी 30 वर्षीय महिला ने बताया कि उसकी शादी शहर की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका अपने पति से अनबन के चलते तलाक हो गया था। जिसके बाद वह गांव अराइयांवाला निवासी फुरकान के संपर्क में आई। आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दो साल पहले आरोपी उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश लेकर गया। जहां उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम रूबीना रख दिया और उसके साथ निकाह कर लिया। आरोपी ने दस्तावेजों में भी उसका नाम चेंज करवा दिया। पीड़िता ने बताया कि जब आरोपी ने उससे निकाह किया तो बताया था कि वह अविवाहित है। मगर निकाह के बाद आरोपी ने शहर की प्रेमनगर कॉलोनी में किराय के मकान में रहने लगा। महिला बोली- पति ने टॉयलेट में भगवान की मूर्तियां बहा दी।

MUNICIPAL COMMITTEE UCHANA (JIND)

S.No	e-Published Date	Closing Date	Opening Date	Title and Ref.No./Tender ID	Organisation Chain
1.	24-Jan-2026 02:30 PM	30-Jan-2026 05:00 PM	02-Feb-2026 11:00 AM	[Cosnt./ Repair of CC/ILPB Patch in Street and Drains Nala and RCC Pulia and Fixing of Iron Jal etc. in Ward No. 01 to 13 in MC Uchana] [20261ECCAFCB EFC3 4196 9B1B 2710EFBAD-BCF352ULB][2026_HRY_498943_1]	Haryana Government|| Urban Local Bodies||MC Uchana
2.	24-Jan-2026 02:30 PM	30-Jan-2026 05:00 PM	02-Feb-2026 11:00 AM	[Construction of Aspirational Toilet in Ward No. 06 of MC Uchana (Re-Tender)] [2026D4DF28EF B46B 4215 985E AED607AAD5352ULB][2026_HRY_498950_1]	Haryana Government|| Urban Local Bodies||MC Uchana

Sd/- Secretary MC Uchana

हरियाणा सरकार

Surajkund Mela Authority

"विकसित भारत का आधार एक आत्मनिर्भर भारत भी है।
आइए, हम सब मिलकर "वोकल फॉर लोकल" को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएँ।"
- नरेन्द्र मोदी

कला और शिल्प का महोत्सव, कौशल, रचनात्मकता, संस्कृति और व्यंजनों का संगम !

39वां सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल

सहभागी राष्ट्र
मिस्त्र

थीम राज्य
Uttar Pradesh
UTTAR PRADESH TOURISM
उत्तर प्रदेश

Meghalaya TOURISM
मेघालय

Local to Global - आत्मनिर्भर भारत की पहचान

31 जनवरी - 15 फरवरी, 2026, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा

आप सभी सादर आमंत्रित हैं

स्थान के लिए QR कोड स्कैन करें

ऑनलाइन टिकट के लिए QR कोड स्कैन करें
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

वेबसाइट के लिए QR कोड स्कैन करें

बुकिंग टिकट सभी मेट्रो स्टेशन व उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध

HARYANA TOURISM Come, holiday with us! | विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS | Ministry of Tourism Government of India | Development Commissioner for Handlooms | ICCR | Utsav | भारतीय हस्तशिल्प Indian handicrafts | Incredible India | MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION | उ.पू.ह.ह.वि.नि. NEHHDC

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा
www.prharyana.gov.in | Follow us on @diprharyana

haribhoomi.com

गणतंत्र दिवस विशेष

हरिभूमि रविवार भारती

छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित

रोहतक, रविवार 25 जनवरी 2026

जब सबके मन में सभी धर्मों के लिए आदर होगा तभी देश-समाज में शांति आएगी

प्रोफेसर अशोक चक्रधर, साहित्यकार

धर्म-जाति के नाम पर सामाजिक विघटन को लेकर मेरा मानना है कि यदि पूरी दुनिया का धर्म एक होता तो लोगों के बीच जाति, धर्म के नाम पर कड़वाहट का प्रश्न नहीं उठता। कोई किसी धर्म का विरोध न करता, पूरी मानवता का एक धर्म होता। धर्म ज्यों-ज्यों वैयक्तिकता की ओर बढ़ता है, त्यों-त्यों उसका स्वरूप खराब हो जाता है। जब समाज के हर व्यक्ति के मन में सभी धर्मों के लिए आदर होगा, तभी देश-समाज में शांति आएगी। यही समस्या भाषा को लेकर भी है। अपनी मातृभाषा सभी को अच्छी लगती है। ऐसे में देश की भाषा कौन-सी है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा है या व्यवहार की भाषा है, उसमें भी लोगों को भ्रम है। दरअसल, भाषा का मुद्दा स्थानीयता से जुड़ा हुआ मामला है।

जहां तक राजनीति और राजनेताओं में द्वेष की समस्या का सवाल है तो यह केवल हमारे देश की चिंता नहीं है, अब यह एक वैश्विक चिंता बन चुकी है। अलग-अलग दल हैं, उनके अपने विधान हैं, विचारधाराएं हैं, अलग-अलग किस्म की लड़ाइयां हैं। ऐसे में जाति, धर्म, भाषा आदि उनके हथियार बन जाते हैं। सच तो यह है कि राजनीति का शुद्ध स्वरूप कभी रहा ही नहीं। हमारे यहां लोकतंत्र है, उसमें संख्या बल है। अब संख्या बल जुटाने के लिए येन-केन प्रकारेण यानी साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरह के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि सत्ता में आने के लिए जीतना जरूरी है। बेशक सभी दल देश की भलाई के लिए जीतना चाहते हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं। लेकिन जब तक तिकड़म नहीं करेंगे तब तक संख्याबल कैसे मिलेगा? संख्याबल के लिए (सत्ता में आने के लिए) ही दलों में राजनीतिक द्वेष होता है। यह दुनिया में सब जगह है।

दुष्प्रचारित भले ही किया जाता है लेकिन हमारा संविधान खतरे में नहीं है। संविधान हम सबको आजादी देता है। अब सवाल यह है कि यह आजादी अपनी नाक बचाने की देता है तो क्या दूसरे की नाक तोड़ने की भी देता है? इसका जवाब है कि आपकी आजादी वहां समाप्त हो जाती है, जहां दूसरे की नाक आ जाती है। चाहे वह नाक फिजिकल, वैचारिक, अपने ईगो की नाक हो या अपने अस्तित्व की। आपको अपने हाथ मर्यादा में रखने होंगे, आपको इतना हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने का अधिकार भी नहीं है कि दूसरे की नाक टूट जाए। कुछ लोग कहेंगे कि अंजाने में टूट गई, क्षमा करें! सच्चाई यह है कि जितने भी अंजाने में नाक तोड़ने के प्रयत्न हैं, वे जान-बूझकर किए जा रहे हैं। आज लोगों को भ्रमित करने के सशक्त माध्यम मौजूद हैं, जो लोगों को विश्वसनीय लगते हैं। आप जिस दल पर विश्वास करेंगे, वही विश्वसनीय लगेगा। लेकिन कोई भी दल पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, वह रह ही नहीं सकता। यह उसकी मजबूरी है। ऐसे में हमें चाहिए ऐसा संविधान, जैसा मुक्तिबोध कहते हैं, 'समस्या एक-मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषणमुक्त कब होंगे?' इसलिए ऐसा संविधान बने, जो सबको सुखी, शोषणमुक्त और सुंदर बना दे। सुंदर आदमी तब होता है, जब वह अंदर से तृप्त हो, अभावग्रस्त न हो, बल्कि भावों से संपन्न हो। *

भारतीय गणतंत्र के समक्ष
वर्तमान चुनौतियां और समाधान

गणतांत्रिक देश बनने के बाद बीते 76 वर्षों में आर्थिक, सामरिक और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में तो हमारे देश ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज में विघटन भी नजर आता है। राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद और द्वेष तो दिखता ही है। बात-बात पर संविधान को खतरे में बताया जाता है, जबकि ऐसा कहने वाले भी अकसर संविधान का उल्लंघन करने से नहीं कतराते। देश के समक्ष उपस्थित इन तमाम चुनौतियों के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? इनके समाधान के लिए किस स्तर पर कैसे प्रयास किए जाने की जरूरत है? इस बारे में अलग-अलग क्षेत्रों की नामचीन शख्सियतों ने साझा किए अपने विचार।

{ विचार }

नैतिकता और देश प्रेम को शिक्षा का हिस्सा बनाना जरूरी है

राकेश सक्सेना, पूर्व न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

आजादी के समय भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। उसके बाद संविधान में कुछ ऐसी बातें आईं कि बहुसंख्यक बैकफुट पर आता चला गया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान में दस साल के लिए आरक्षण की बात कही, जो आज भी चल रहा है। हाल यह है कि अब न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है न किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता, जबकि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए था। लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने से भले देश कमजोर होता हो लेकिन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। समाज को वसुधैव कुटुंबकम और मानवता की बात सिखाई जानी चाहिए। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के जो मूलभूत सिद्धांत थे (छात्रों को नैतिकता, राष्ट्रभक्ति, सहिष्णुता के संस्कार देना) वो आज की शिक्षा व्यवस्था में गौण हो चुके हैं। बस ज्यादा कमाने की होड़ है, ऐसे में नैतिकता, सामाजिक हित और देश प्रेम को शिक्षा का हिस्सा बनाना जरूरी है। शिक्षा ग्रासरूट पर काम करके नैतिकता व जीवन मूल्यों को सिखाने का सशक्त माध्यम है।

यह सही है कि गांधीजी का अपना सिद्धांत था। लेकिन देश को आजाद कराने में अहिंसात्मक आंदोलन और क्रांतिकारियों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन दोनों की भूमिका रही। आजादी के बाद एक वर्ग के लोगों को सत्ता मिली, लेकिन वे लोग जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी जान लगा दी। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, सुभाषचंद्र बोस जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को देश में वह मान-सम्मान नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था। ये बातें देश के लोग जानते हैं इसलिए समाज में मतभेद है।

हालांकि देश में कुछ लोग सच में राष्ट्रहित चाहते हैं, राष्ट्रप्रेमी हैं। लेकिन यह बड़ी विडंबना है कि कुछ लोगों को देश के खिलाफ बोलने में ही एक वर्ग विशेष का समर्थन मिल रहा है। इससे राजनीतिक द्वेष बढ़ रहा है। अब यह द्वेष केवल देश का आंतरिक मामला नहीं रहा, इसे बाहर से भी बढ़ावा मिल रहा है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। बाहर से नैरेटिव आते हैं और फिर कुछ लोग उस नैरेटिव के अनुसार देश के खिलाफ बोलने में खुद को बहुत एडवांस समझते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए यह बहुत खतरनाक स्थिति है।

मेरा मानना है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। कुछ संशोधन राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि संविधान में यदि सभी को बोलने की आजादी दी गई है तो उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। आज संविधान में नागरिक कर्तव्यों को दरकिनार कर संविधान को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई आजादी के नाम पर अभद्र भाषा व देशविरोधी धमकी तक दे देता है। उसके साथ कुछ नहीं होता जबकि ऐसे में राष्ट्रसुरक्षा से जुड़ा केस तक चलाया जा सकता है, यह कानून में है। लेकिन ऐसा नहीं होता। संविधान की आड़ में राष्ट्र विरोध में काम करने वालों को सपोर्ट मिल रहा है। चिंताजनक है कि वे लोग संविधान खतरे में है, ऐसा बोलकर अपनी स्वार्थ की रोटियां सेंक रहे हैं। *

शिक्षा-जागरूकता से ही खत्म हो सकता है धर्म-जाति भेद

ऋतु सारस्वत, समाजशास्त्री

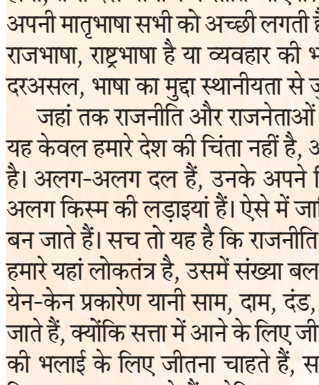

यह चिंताजनक बात है कि भारत में जो सामाजिक असमानताएं हैं, वो निरंतर प्रयास के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। दरअसल, अधिकांश क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय दल, सभी में राजनीतिक स्वार्थ इतना गहरा है कि धर्म, जाति व क्षेत्रवादी राजनीति करते हैं। भाषा की राजनीति ने तो भारत की आत्मा को छलनी कर दिया है। युवा पीढ़ी इस राजनीति की इस कदर शिकार हो रही है कि वह अपनी पहचान तक के लिए लड़ रही है कि क्या मैं भारत का ही निवासी हूं? यह स्थिति पीड़ादायक है। इस भाषा की राजनीति को जल्द रोकना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया के वो इंफ्लूएंसर, जो बिना तथ्यों को समझे गलत जानकारी, भ्रम, अफवाहें फैलाकर समाज में नकारात्मक और ध्रुवीकरण की भावना को फैला रहे हैं, वे भी हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़े बाधक हैं। इनके अलावा हमारी शिक्षा नीति में नैतिक व नागरिक मूल्यों की चर्चा बहुत कम है। ऐसे में विद्यार्थी रोजगार के लिए प्रोफेशनल रूप से तो तैयार हो रहे हैं लेकिन नैतिक आचरण के मूल भाव को नहीं सीख पाते। हमारी शिक्षा नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता और वैज्ञानिक सोच को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। विकास की योजनाएं ऐसी हों, जो असमानता को दूर कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, तभी विघटन दूर होगा। हालांकि मुझे समाज में जाति भेद जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है। इसमें अभी समय लगेगा और यह काम केवल शिक्षा व जागरूकता से ही संभव है। सत्ता ऐसा नशा है, जिसे व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता और इसे पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे सभी हथियारों का प्रयोग करता है। आज कुछ लोग इसके लिए राष्ट्रहितों की तिलांजलि देने तक से पीछे नहीं हटते हैं। संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। इस समस्या का समाधान यही है कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में आ रहे हैं, उनके बजाय पढ़े-लिखे नेता राजनीति में आएं। राजनीति के लिए भी एक न्यूनतम शिक्षा होना अनिवार्य है। जिस प्रकार बाकी क्षेत्रों में ओरिएंटेशन होता है, वैसे ही राजनीति में भी हो, ताकि उन्हें आभास हो सके कि जिस व्यवस्था में वे आए हैं, वहां उनसे क्या अपेक्षा है और क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए? इसके साथ ही राजनीतिक समाजीकरण की भी बहुत आवश्यकता है। यह पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। इससे लोगों को पता चलेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कौन-कौन से साधन हो सकते हैं। साथ ही ऐसी कौन-सी अवधारणाएं, विचारधाराएं हैं, जो व्यवस्था में कुठाराघात कर रही हैं?

संविधान खतरे में है, यह कहना हास्यास्पद है। जब कोई नेतृत्व में बैठा व्यक्ति यह कहता है तो एक बार वह स्वयं यह विश्लेषण भी कर ले कि संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ कर्तव्यों की बात भी है। अगर संविधान खतरे में है तो इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कमी रखी है, तभी संविधान खतरे में है। *

समाज बांटने वालों का जनता स्वयं तिरस्कार करे

प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत, पूर्व निदेशक-एनसीईआरटी

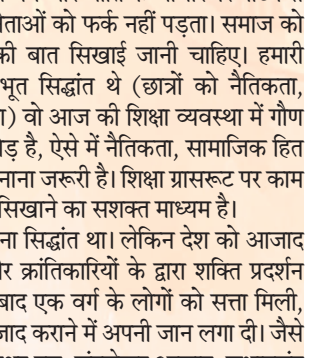

धर्म, जाति व भाषा के विवाद को मैंने लंबे समय से देखा है। यह देश में धीरे-धीरे राजनीति के कारण फैलाया गया। मैंने सभी शिक्षा नीतियों का अध्ययन किया है। सन 1974 से देश-विदेश की महत्वपूर्ण शिक्षा बैठकों का हिस्सा रहा हूं। आजादी के शुरुआती 3-4 दशकों में जो सरकारें बनीं, वे भाषा की समस्या का ऐसा समाधान नहीं निकाल पाईं, जिससे इन प्रवृत्तियों को रोका जाता। देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो कॉन्सेप्ट आया, वह लोगों को अलग करने और अविश्वास पैदा करने में भागीदार रहा। अब अगर आप गांव के स्कूल में कुछ बच्चों को साइकिल, कुछ को वजीफा देंगे और कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं देंगे, तो उन मासूम छोटे बच्चों के अंदर कैसी भावना पैदा होगी? हमें इस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम इस तरह का कोई भेदभाव बच्चों के बीच करते। सहायता दीजिए लेकिन उस तरीके से दीजिए कि एक वर्ग के लोगों को ऐसा न लगे कि मैं ही क्यों छूट गया? मैं जापान का उदाहरण अकसर देता हूं। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद वह देश मनोबल और भौतिक स्तर पर टूट गया था। लेकिन उन्होंने अपने स्कूलों के अध्यापकों को तैयार किया और उन्होंने बच्चों को कहा कि अब तुम्हें देश बनाना है। जब तक आपके अध्यापकों को यह पता न चले कि मैं देश का निर्माता हूं, देश का भविष्य बना रहा हूं, तब तक यह अविश्वास बढ़ता रहेगा। यदि हम आजादी के बाद यह भेदभाव न करते तो यह स्थिति न होती। हमने संवेदनशीलता के साथ इस पक्ष का विवेचन नहीं किया। वास्तव में समाज के अलग-अलग वर्गों में बढ़ती दूरी जैसी समस्याएं, आज पैदा नहीं हुई हैं, इनका इतिहास है। जब आपको पिछला पता नहीं होगा, तो आप एक तरफा ही देख सकेंगे। पहले वे लोग, जिन्होंने देश को धर्म और जाति में बांटा, वे जिम्मेदार हैं और आज जो बांट रहे हैं, वे भी जिम्मेदार हैं।

मेरा मानना है कि बच्चों और युवाओं को यह बताना चाहिए कि दुनिया की सभी समस्याओं के पीछे कहीं न कहीं धर्म आ ही जाता है और दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान भी धर्म ही है। समाधान यह है कि हर नागरिक के मन में यह भाव पले कि मेरे लिए मेरा धर्म सबसे अच्छा और आपके लिए आपका। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब छोटे बच्चों को हम यह सिखाएंगे कि आपके बगल में बैठे बच्चे का धर्म भी उतना ही महान है, जितना आपका तो उसके मन में सभी धर्मों को लेकर सम्मान रहेगा। यही एक तरीका है, जो सामाजिक विघटन को रोक सकता है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि जो नेता किसी भी आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करे, जनता स्वयं उसका तिरस्कार करे। आज का एक बड़ा विरोधाभास यह है कि जो संविधान की मर्यादाओं को स्वयं नहीं मानते, वही कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, ऐसा भ्रम फैलाने वालों को जनता अच्छी तरह जानती-समझती है। इसलिए वही ऐसे लोगों को सबक सिखा सकती है। *

प्रस्तुतिः रेनू खंतवाल

गीत

प्रो. शरद नारायण खरे

शूरवीर भारत की सेना

जिसने हर मुश्किल में भी कर डाला शत्रु-दमन।
शूरवीर भारत की सेना, करते सभी नमन।
नहीं जान की कोई फिक्र की, बस सीमा देखी।
निज गृह की परवाह नहीं की, बस हिम्मत देखी।।
भारत की सेना देख करें घुसपैठी त्वरित गमन।
शूरवीर भारत की सेना, करते सभी नमन।।
आशाओं के दीप जलाकर, हमको राहत नित दी।
सर्दी, गर्मी, बारिश में भी, हमको हिम्मत नित दी।।
हे सेना! भारत की अनुपम, तुमने किया चमन।
शूरवीर भारत की सेना, करते सभी नमन।।
अंधकार में प्रखर रोशनी, रहते सीना ताने।
सचमुच में हम विश्वविजेता, भले न कोई माने।।
भारत की सेना का अर्पित हरदम तन और मन।
शूरवीर भारत की सेना, करते सभी नमन।।
तीज और त्योहार सभी ही सीमा पर हैं मनते।
अगर पड़ोसी आंख दिखाए, पलट प्रहार फिर सहते।।
सदा तिरंगा हाथों में, अधरों पर जन-गण-मन।
शूरवीर भारत की सेना, करते सभी नमन।।
ईद, दिवाली, होली तुमसे, ओ' भारत की सेना।
तुमने तो सीखा है हरदम, केवल सेवा देना।।
वजह तुम्हीं हो, जिसके कारण महक रहा गुलशन।
शूरवीर भारत की सेना, करते सभी नमन।।

{ व्यंग्य / सूर्यकुमार पांडेय }

अब सेल्फ सर्विस ही देश सेवा

आज के दौर में देश सेवा के नाम पर अधिकांश अंतरी से लेकर संतरी तक सेल्फ सर्विस करने की ही जुगाड़ में लगे रहते हैं। यही वजह है कि वास्तव में देश सेवा करने वाले लोग खुद को बेबस और असमंजस में महसूस करते हैं। ऐसे ही टेंशनियाए हुए भाई जी की दास्तान।

भाई जी को देश की चिंता है। वह अपना दुःखड़ा किसे सुनाएं? समाज व्यक्तिवादी होता जा रहा है। नई जनरेशन अपने में मगन है। पुरानी का आचरण अनुकरणीय नहीं रहा। देश की राजनीति लाफ्टर शो हो चुकी है और मीडिया सनसनीखेज न्यूज परोसने में व्यस्त है।

भाई जी का कहना है, यहां हर कोई मनमानी कर रहा है। अंतरी से संतरी तक इसे लूटने में लगे हैं। पगले की भैंस ब्याई है, सब बाल्टी लेकर दौड़ रहे हैं। लोगों के हाथ लंबे और जेबें चौड़ी हो चुकी हैं। अब कोई 'अंडरलैंड डीलिंग' नहीं होती। खुला खेल फरक्खाबादी है।

भाई जी को टेंशनित पाकर मैंने उन्हें सुझाव थमाया, 'आप स्वयं की एक संस्था बना लीजिए, चंद बचे-खुचे समर्पित लोगों को जोड़िए, देश के लिए सार्थक काम कीजिए। तमाम लोग यही कर रहे हैं। जिनके पास खुद के एनजीओज हैं, वे मौज में हैं। उग-पनप रहे हैं। आप भी सरकारी एड हथियाइए और फलिए-फूलिए। इन दिनों स्वयंसेवा ही देश-सेवा है। भुक्खड़ रहनुमा हो गए हैं। 'भूखे भजन न होहिं गोपाला, इस नाते वे अपना पेट भर रहे हैं। पहले स्वयं खा-पीकर मुटा लें, इस लायक तो हो लें कि चल-फिर सकें, तब करेंगे कुछ काम। यों भी कड़ी मेहनत का काम है देश-सेवा। इसके लिए पर्याप्त एनर्जी की आवश्यकता होती है। लोग वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। प्राकृतिक और भौतिक रिसोर्सेज को दुह रहे हैं। ऊर्जा की मलाई चांपते इन जनसेवकों को आप भी अपना आइडियल बनाइए।'

भाई जी की फिक्रमंद खोपड़ी में मेरी यह एडवाइस लगभग-लगभग घुसी। वह कहने लगे, 'मैंने एक बार एक संस्था बनाई थी। चंदा-वंदा भी कलेक्ट किया था। सरकारी अनुदान की जुगत भी भिड़ाई थी। सारा गुड़-गोबर हो गया। चंदे में चींटे लग गए। इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी अनुदान प्राप्त करने में खप गया। भैये, यह संस्था वाला धंधा अपने बूते का नहीं है। कुछ नया करना होगा।'

भाई जी की चिंता कैसे सॉल्व हो, अब यह देश की चिंता का विषय है। प्रॉब्लम यह है कि भाई जी को खुला खेल पसंद नहीं है। *

{ लघुकथा / विनय कुमार पाठक }

बेबसी

काफी देर से बिंदी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। गांव में पक्की सड़क थी नहीं। शहर को जाने वाली मुख्य सड़क ढाई किलोमीटर दूर थी। बिंदी का पति मंगरू घबरा रहा था। क्या उपाय किया जाए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर गांव के लोगों ने आनन-फानन में बहंगी बनाई और बिंदी को लेकर किसी तरह पक्की सड़क तक पहुंचे। ढाई किलोमीटर की दूरी तय करने में काफी समय लग गया। इस बीच बिंदी दर्द से कराहती रही। सड़क तक पहुंचने के बाद किसी तरह एक वाहन की व्यवस्था कर उसे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार कर उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यह सब करने में काफी देर हो गई। सदर अस्पताल पहुंचते-पहुंचते अधिक रक्तस्राव होने के कारण बिंदी और उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की सांसें थम गईं। मंगरू बदहवास-बेबस सा अपनी पत्नी के शव के बगल में सिर थाम कर बैठ गया। उसका मुख एकदम से मलिन हो गया था। वहीं बगल की दीवार पर एक पोस्टर चिपका था, जिस पर लिखा था, 'आपका स्वास्थ्य, हमारी जिम्मेवारी।' पोस्टर पर ही राज्य के मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के मुस्कुराते चेहरे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे मंगरू की बेबसी पर मुस्कुरा रहे हों। *

{ पुस्तक चर्चा / विज्ञान भूषण }

रोशनी की शिनाख्त

वर्तमान हिंदी साहित्य के परिदृश्य में शीर्षस्थ व्यंग्यकारों में ज्ञान चतुर्वेदी भी प्रतिष्ठित हैं। उनकी व्यंग्यात्मक दृष्टि इतनी गहरी और पैनी है कि अपने आस-पास के समाज में पैबस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्रूप की भी वे शिनाख्त करके हमारे सामने ले आते हैं। उनके ऐसे ही कुछ धारदार व्यंग्यों का संकलन 'रोशनी की शिनाख्त' हाल में छपकर आया है। हिंदुस्तान में हिंदी और हिंदी दिवस की दुर्दशा पर करारा कटाक्ष 'साहब और हिंदी' में किया गया है। 'दरअसल आज हिंदी डे है। आज से सरकारी दफ्तरों में हिंदी सेलिब्रेशन पखवाड़ा शुरू होगा।' वर्तमान स्वतंत्र-गणतंत्र भारतवर्ष में गांधीजी कितने प्रासंगिक हैं, इसे समझने के लिए 'गांधी जी की गवाही' व्यंग्य को पढ़ा जा सकता है। इसकी ये पंक्तियां देखने योग्य हैं, 'गांधी जी को मरा बोलते शर्म नहीं आती? वे जिंदा हैं और रहेंगे। अपने पर्स में झांक कर देखो। गांधी जी हैं कि नहीं?' देश की नसों में समायी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को लेखक ने पूरी निर्ममता से 'घोटालों का गणित' में उजागर किया है। एक सवाल में ही इसकी बानगी देखी जा सकती है, 'यदि कोई मंत्री खनिज खोदने और रेत बिकवाने से हजार करोड़ बनाने की ठान ले तो सारा प्रदेश खोद डालने में उसे कितने साल लगेंगे?'

पुस्तकः रोशनी की शिनाख्त, लेखकः ज्ञान चतुर्वेदी, मूल्यः 350 रुपए, प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

इस पुस्तक से गुजरते हुए स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इन व्यंग्यों के कटाक्षों से उत्पन्न होने वाली रोशनी इतनी तेजमय है, जिनसे हमारे देश-समाज की राजनीति, शासन-प्रशासन और तंत्र के अंधेरे-कोनों में भी ढंकी-तुपी विडंबनाओं और विसंगतियों की शिनाख्त आसानी से की जा सकती है। *

ट्रैवलिंग का नया ट्रेंड

स्टॉप ओवर टूरिज्म

एक ही यात्रा के दौरान एक से अधिक देशों या शहरों की संस्कृतियों का अनुभव करने का एक किफायती तरीका है स्टॉप ओवर टूरिज्म। इन दिनों ट्रैवलिंग के शौकीन लोगों और पर्यटन उद्योग में 'स्टॉप ओवर टूरिज्म' का क्रेज बढ़ रहा है। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर ट्रैवलिंग के इस नए ट्रेंड के बारे में जानिए।

{ ट्रैवलिंग / शिखर चंद जैन }

पर्यटन उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। नई तकनीकों, सस्ती उड़ानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कारण यात्रा पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई है। इस बदलते परिदृश्य में, 'स्टॉप ओवर टूरिज्म' एक नया और आकर्षक मॉडल बनकर उभर रहा है। यह न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद और अनूठा अनुभव प्रदान करने वाला है, बल्कि विभिन्न देशों के पर्यटन को भी बढ़ावा देता है।

क्या है स्टॉप ओवर टूरिज्म: स्टॉप ओवर टूरिज्म का अर्थ है कि यात्री अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले किसी मध्यवर्ती स्थान पर कुछ समय बिताते हैं, जिसे आमतौर पर लंबी उड़ानों के दौरान 'लेओवर' के रूप में जाना जाता है। इसके तहत हवाई यात्री अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय, बीच में पड़ने वाले शहर या देश में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रुकते हैं और वहां के पर्यटन स्थलों का आनंद लेते हैं।

एयरलाइंस दे रही सुविधाएं: कई एयरलाइंस, जैसे एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस और टर्किश एयरलाइंस, स्टॉप ओवर पैकेज ऑफर करती हैं, जिसमें होटल, टूर और वीजा सुविधाएं शामिल होती हैं। विश्व भर में कई देश और शहर भी स्टॉप ओवर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यह उनकी अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को मजबूत करता है।

देश में स्टॉप ओवर टूरिज्म की संभावनाएं: भारत, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता, और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण, स्टॉप ओवर टूरिज्म के लिए एक आदर्श गंतव्य हो सकता है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ वैश्विक हब के रूप में उभर रहे हैं। भारत में स्टॉप ओवर टूरिज्म की संभावनाओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

दिल्ली: दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण एशिया का एक प्रमुख हब है। ऐसे में विदेशी यात्री, स्टॉप ओवर पर्यटक के रूप में कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा जैसे अनेक ऐतिहासिक स्थल और स्थानीय बाजारों जैसे चांदनी चौक का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली के नजदीक आगरा (ताजमहल, फतेहपुर सीकरी) और जयपुर (हवा महल, आमेर का किला) जैसे गंतव्यों को भी छोटे टूर पैकेज में शामिल किया जा सकता है।

मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित मरीन ड्राइव

मुंबई: मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। स्टॉप ओवर यात्री अपनी यात्रा के दौरान यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और एलिफेंटा गुफाओं का भ्रमण कर सकते हैं। बॉलीवुड स्टूडियो टूर भी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आकर्षक हो सकता है।

बेंगलुरु: बेंगलुरु का केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तेजी से वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। स्टॉप ओवर यात्री लालबाग बोटेनिकल गार्डन, बेंगलुरु पैलेस जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। टूरिस्ट्स के स्टॉप ओवर पैकेज में पास में स्थित मैसूर या कुर्ग जैसे गंतव्यों को भी शामिल किया जा सकता है।

केरल और गोवा: दक्षिण भारत के राज्य केरल में स्थित कोचीन और महाराष्ट्र के निकट गोवा एयर पोर्ट उन यात्रियों को आकर्षित कर सकते हैं, जो समुद्र तटों, बैकवाटर्स और आरामदायक अनुभव की तलाश में रहते हैं।

दुनिया के चर्चित स्टॉप ओवर टूरिज्म सेंटर: दुनिया के कुछ स्थान तो स्टॉप ओवर टूरिज्म के खास केंद्र बन गए हैं-

दुबई (संयुक्त अरब अमीरात): दुबई ने स्टॉप ओवर टूरिज्म को एक ट्रैवल अट्रैक्शन के रूप में विकसित किया है। एमिरेट्स एयरलाइंस के माध्यम से, यात्री मुफ्त या रियायती स्टॉप ओवर पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रणनीतिक स्थिति और विश्वस्तरीय सुविधाएं इसे स्टॉप ओवर के लिए आदर्श बनाती हैं।

सिंगापुर: सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक है, स्टॉप ओवर यात्रियों के लिए मुफ्त सिटी टूर प्रदान करता है। सिंगापुर ने अपने छोटे आकार के बावजूद, मरीना बे सैंड्स, गार्डंस बाय द बे और सेंटोसा द्वीप जैसे आकर्षणों के साथ स्टॉप ओवर टूरिज्म को लोकप्रिय बनाया है।

दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किला

आइसलैंड: आइसलैंड एयर ने स्टॉप ओवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई है, जिसमें यात्री यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच यात्रा करते समय आइसलैंड में सात दिनों तक बिना अतिरिक्त किराए के रुक सकते हैं। *

स्टॉप ओवर टूरिज्म के होते हैं कई तरह के लाभ

स्टॉप ओवर टूरिज्म के कई लाभ हैं, जो इसे यात्रियों, स्थानीय अर्थव्यवस्था और एयरलाइंस के लिए फायदेमंद बनाते हैं। यात्रियों को लंबे लेओवर का उपयोग करके नया गंतव्य देखने का अवसर मिलता है। छोटे टूर पैकेज थकाऊ यात्रा को रोमांचक बनाते हैं। सस्ते या मुफ्त पैकेज यात्रियों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। स्टॉप ओवर यात्री होटल, रेस्टोरेंट्स, परिवहन और स्थानीय दुकानों में खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यह पर्यटन उद्योग में रोजगार सृजन करता है। स्टॉप ओवर प्रोग्राम एयरलाइंस को प्रतिस्पर्धी लाभ देते हैं। हवाई अड्डों पर यात्री खर्च (शॉपिंग, भोजन) से राजस्व बढ़ता है।

{ जानकारी / के. पी. सिंह }

भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है। जंगल का राजा शेर है और यह भारतीय वन क्षेत्र में पाया भी जाता है, फिर बाघ को ही क्यों चुना गया राष्ट्रीय पशु? इस प्रश्न के उत्तर समेत कुछ और रोचक जानकारियां यहां दे रहे हैं।

साहस-आत्मनिर्भरता का प्रतीक

हमारा राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर

हर वर्ष जब भी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस आता है, तो इस अवसर पर आयोजित होने वाली परेड की कदमताल के साथ भारत की एक अदृश्य परेड भी साथ-साथ हमारे मन में चलती है और यह परेड होती है, हमारी पहचान की। तिरंगा, संविधान, अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान और फिर उन प्रतीकों की लंबी कतार, जिन्हें देखकर भारत को भारत के रूप में पहचाना जाता है। इन्हीं प्रतीकों में से एक ऐसा प्रतीक भी है, जिसकी मौजूदगी में पूरा जंगल डोल उठता है और वह है- हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर को अपने देश का राष्ट्रीय पशु चुने जाने की कहानी केवल एक पशु को राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल किए जाने की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस दौर की, जब गणतंत्र बनने के बाद हमने महसूस किया कि गणराज्य सिर्फ संसद और चुनाव नहीं होते। गणराज्य का आत्मसम्मान उसके जंगलों, नदियों और जीवों में भी धड़कता है।

इसलिए चुने गए प्रतीक: भारत 1950 में गणतांत्रिक राष्ट्र बना। लेकिन गणराज्य बन जाना और गणराज्य की पहचान बन जाना, ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए भारत पहले गणराज्य बना और फिर धीरे-धीरे गणराज्य की पहचान में ढला। इसी क्रम में भारत ने अपने प्रतीक तय किए। जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु आदि। राष्ट्रीय पशु के जरिए हमने यह घोषित किया कि हमारी धरती सिर्फ हमारे शहरों की नहीं, हमारे जंगलों की भी है और उस धरती की रक्षा केवल सीमाओं पर नहीं सीमाओं के भीतर भी होती है।

दिखते हैं संप्रभु गणराज्य के गुण: भारत ने जब बाघ को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल कर राष्ट्रीय पशु चुना तो इस चयन में हमने अनजाने ही अपने राष्ट्रीय स्वभाव के कुछ सबसे चमकीले गुण चुन लिए। ये गुण हैं- साहस के, गरिमा के, ताकत के, आत्मनिर्भरता के और अपनी सीमा के संरक्षण के। दरअसल, बाघ बिना शोर-शराबे के साहस का प्रतीक होता है। बाघ शक्तिशाली होता है, लेकिन क्रूर नहीं। बाघ में आत्मनिर्भर होने का स्वभाव होता है। वास्तव में हम एक संप्रभु गणराज्य के तौर पर अपने इन्हीं गुणों को दर्शाना चाहते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के मूल गुण हैं।

बाघ क्यों, शेर क्यों नहीं: यह प्रश्न अकसर किया जाता है कि ब्रिटेन, सिंगापुर, नीदरलैंड जैसे कई देशों ने शेर को अपना राष्ट्रीय पशु बनाया है। भारत के जंगलों (गुजरात के गिर के जंगलों) में भी शेर हैं। तो फिर हमने अपने राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर को क्यों नहीं चुना, हमने बाघ को क्यों चुना? कारण सीधा था, बाघ भारत की प्राकृतिक पहचान के साथ जुड़ा है। बाघ भारत के भूगोल में फैला हुआ है। पहाड़, तराई, मध्य भारत, पूर्वोत्तर और सुंदरवन आदि सभी जगहों पर इसकी उपस्थिति है। इसका दूसरा कारण भी रहा कि बाघ संकट में था। शिकारियों द्वारा अंधाधुंध शिकार के कारण, जंगलों की कटाई के कारण, अवैध तस्करी के कारण, भारत में बाघ की संख्या धीरे-धीरे खतरनाक ढंग से घट रही थी। ऐसे में प्रतीक चुनना सिर्फ गर्व की बात नहीं थी, जिम्मेदारी का भी सबब था, जिसे सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत थी, उसी को अपना राष्ट्रीय पशु चुनना, निश्चित तौर पर यह एक सोच-समझकर उठाया गया कदम था।

इस तरह हुआ अमल: बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1972-73 में मिला। इसी के साथ अपने राष्ट्रीय प्रतीक पशु को बचाने के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया। बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने के पीछे का उद्देश्य था- बाघ को बचाने के लिए नीति निर्माण, सुरक्षा ढांचा और जन भागीदारी बनाना। 'प्रोजेक्ट टाइगर' के बाद टाइगर रिजर्व, निगरानी, शिकार रोधी व्यवस्था, वन्यजीव संरक्षण कानूनों की मदद से बाघों के संरक्षण के प्रयास को सार्थक गति मिली।

संस्कृति से नाता: बाघ केवल वन्यजीव भर नहीं है, इसका हमारी सांस्कृतिक विरासत से गहरा नाता है। यह हमारी सांस्कृतिक स्मृति में रचा-बसा शक्ति स्रोत है। लोककथाओं, जनश्रुतियों में, हमारी कहावतों में, राज दरबारों में, दीवारों में, आदिवासी घरों में बनाए जाने वाले चित्रों में, हर जगह बाघ की मौजूदगी है। बाघ का डर जंगल को मर्यादित करता है और मर्यादा जंगल को जंगल बनाती है। शायद इसलिए भारत की परंपरा में बाघ खौफ का नहीं, सम्मान का पात्र रहा है और इसे हम आतंक नहीं, अनुशासन से चिन्हित करते रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे हमारे देश में संविधान या कानून का डर नहीं, कानून का शासन और अनुशासन है। जब बाघ दहाड़ता है तो जंगल कांपता है। लेकिन जब बाघ चुपचाप चलता है तो जंगल समझ जाता है कि शक्ति का सही अर्थ क्या है! ठीक उसी तरह जैसे गणराज्य की असली ताकत परेड में नहीं, अपने नागरिकों के विवेक, अपने जंगलों के संरक्षण और संवैधानिक मर्यादा में होती है। इस तरह हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ न केवल जंगलों की रखवाली करता है, हमारे स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। *

भले ही आज देसी-विदेशी और मॉडर्न ट्रेंड के कई रेस्टोरेंट्स का देश के महानगरों में क्रेज है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह रहे और पारंपरिक व्यंजनों से मेहमानों का स्वागत करते हैं।

पारंपरिक स्वाद परोसते ये

ऐतिहासिक भारतीय रेस्टोरेंट

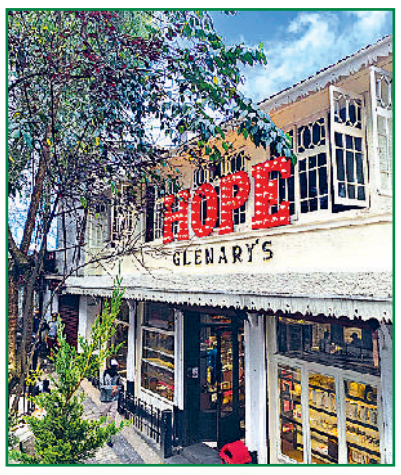

{ धरोहर / समीर चौधरी }

अपने देश में आज भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जो न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के गवाह हैं बल्कि देश की आजादी के बाद बदलते हुए फूड ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और खाने की आदतों के बावजूद भी मजबूती के साथ अपने अस्तित्व व महत्व को बनाए हुए हैं। ये भारत के सबसे पुराने रेस्टोरेंट हैं, जो अब भी यहां आने वाले मेहमानों को इतिहास से रूबरू कराते हैं। इनका महत्व केवल यही नहीं है कि ये पुराने हैं बल्कि ये भरोसेमंद भी हैं। इनकी रेसिपी स्थिर रही हैं, ये अपने स्वाद व आइकोनिक डिशेज के लिए आज भी विख्यात हैं। ये रेस्टोरेंट भोजन के साथ यादें भी परोसते हैं, आजादी के संघर्ष की यादें।

इंडियन कॉफी हाउस

नई दिल्ली में राजीव चौक के निकट स्थित इंडियन कॉफी हाउस की स्थापना 1876 में हुई थी। यह कैफे कम और सांस्कृतिक संस्था अधिक है। इसकी बेंटवुड कुर्सियां, सफेद लिबास में वेटर और कॉफी के कप, जिनके साथ अनंत बहसें हो चुकी हैं, गवाह हैं कि यह लेखकों, छात्रों, क्रांतिकारियों और शिक्षाविदों की मुलाकातों का अड्डा है। यहां का मेनू साधारण है, कटलेट्स, आमलेट, फिल्टर कॉफी, लेकिन इनका स्वाद कोई नहीं भूल पाता है। यहां पॉपुलर कॉफी ड्रिंक्स की बड़ी रेंज उपलब्ध है।

ग्लेनारीज

दार्जिलिंग में 1911 में ग्लेनारीज रेस्टोरेंट स्थापित हुआ था। इसकी शुरुआत बेकरी के रूप में हुई थी, तब वहां यूरोपीय शैली के ब्रेड व पेस्ट्री परोसे जाते थे। समय के साथ इसका विस्तार फुल-सर्विस रेस्टोरेंट और टी रूम के तौर पर हुआ। नेहरू रोड पर स्थित यह अपने बेकरी उत्पादों, डेजर्ट्स और कॉन्टिनेंटल शैली की डिशेज के लिए विख्यात है। ग्लेनारीज आज भी अपनी मूल बिल्डिंग में ही मौजूद है। यह स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को सेवा प्रदान करने वाला दार्जिलिंग का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है।

ब्रिटानिया एंड कंपनी

मुंबई के ऐतिहासिक डॉक्स के निकट ब्रिटानिया एंड कंपनी है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। यह अपने साथ पारसी समुदाय का सम्मान लेकर चलता है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। यह रेस्टोरेंट बेरी पुलाव, कैरामल कस्टर्ड और ईरानी शैली की मेहमाननवाजी के लिए विख्यात है। इस रेस्टोरेंट को जल्दबाजी पसंद नहीं है। ऑर्डर्स धीमे से लिए जाते हैं, राय आजादी से दी जाती है और समय शालीनता से चलता है। इसने आर्थिक उतार-चढ़ाव, फूड ट्रेंड्स और पीढ़ीगत परिवर्तन देखे, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदली।

फ्लुरीज टी रूम

कोलकाता की फैशनेबल पार्क स्ट्रीट पर लीजेंडरी टी रूम फ्लुरीज की स्थापना स्विस कपल जे फ्लुरीज ने 1927 में की थी। भारत में ब्रंच का फैशन आने से बहुत पहले यूरोप का पेस्ट्री कल्चर, यहां लेकर आने का श्रेय फ्लुरीज को ही जाता है। उस दौर में यह बर्थडे, डेटिंग और खामोश दोपहर बिताने के लिए विख्यात हो गया। आज भी यहां लोग चाय के साथ पेस्ट्री खाना पसंद करते हैं। बदलते मेनू के साथ मूल परंपरा का वैभव बरकरार है। फ्लुरीज में सिर्फ नॉस्टैल्जिक फील नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड भी बरकरार है, जिसकी वजह से यहां आने वाले ग्राहक उस पर अब भी विश्वास करते हैं।

कैफे टाटो

गोवा के मडगांव में 1913 में सामान्य उपहार गृह के रूप में शुरू हुआ था कैफे टाटो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मडगांव का सबसे प्रख्यात फूड इंस्टिट्यूशन बन गया है। इसे सौ साल से

अधिक हो गए हैं गोवा के लोगों और पर्यटकों को पूरी, सूखी सब्जी, बन और भाजी खिलाते हुए। यह फूड रूटीन बन गया है। निरंतरता कैफे टाटो की पहचान है। यहां के मेन्यू ने ट्रेंड्स का पीछा नहीं किया है। स्वाद आज भी वही बरकरार है, जो दशकों पहले हुआ करता था। यह हेरिटेज शोकेस नहीं बल्कि लिविंग कैफे है। यहां एक बार खाया खाना आप हमेशा याद रखेंगे।

मवाल्ली टिफिन रूम

मवाल्ली टिफिन रूम (एमटीआर) अति अनुशासित अंदाज में दक्षिण भारत के फूड का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रिटिश पाबंदियों के दौरान बैंग्लुरु में 1924 में स्थापित हुआ। इस रेस्टोरेंट ने संतुलित घी, खमीरी बैटर और नियंत्रित मसालों के साथ नाश्ता संस्कृति को नया रूप दिया। एमटीआर साबित करता है कि सादगी का जब सम्मान किया जाता है तो लंबे समय तक लोग उसे पसंद करते रहते हैं। *

{ सिने ट्रेंड / हेमंत पाल }

लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर हिंदी सिनेमा ने शुरुआत से ही बहस चलाई है। कभी आजादी के आदर्शों के जरिए, कभी भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ तो कभी संविधान की धाराओं को फिल्म की कहानियों में पिरोकर। इन फिल्मों ने दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि वोट, अभिव्यक्ति, समानता, असहमति और न्याय जैसे अधिकारों के बारे में जागरूक भी किया है। समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय जैसी भारतीय संविधान की मूल भावना कई हिंदी फिल्मों के कथानक में प्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक रूप से उपस्थित रही है।

लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करती 'लीडर': आजादी के बाद की आर्थिक असमानताओं और भ्रष्टाचार ने फिल्मों को लोकतांत्रिक अधिकारों पर टिप्पणी करने के लिए कई बार प्रेरित किया। सन 1964 की फिल्म 'लीडर' ने चुनाव, भ्रष्टाचार और मताधिकार पर सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। फिल्म में नायक (दिलीप कुमार) एक आदर्शवादी पत्रकार और नेता के रूप में सामने आता है, जो चुनावी धांधलियों, फर्जी वोटिंग और जनता की आवाज दबाए जाने के खिलाफ लड़ता है। यह सीधे मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों की ओर संकेत करता है। दर्शक यहां समझते हैं कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का तंत्र नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक की सक्रिय भागीदारी भी है, जो सत्ता से सवाल पूछे और चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ खड़ा हो।

इमरजेंसी की झलक दिखाती 'किस्सा कुर्सी का': सत्तर के दशक के अंत में बनी कुछ फिल्मों ने सेंसरशिप और इमरजेंसी के दौर की कथित दमनकारी राजनीति पर तीखी टिप्पणी की थी। 1978 में आई 'किस्सा कुर्सी का', 'नसबंदी' जैसी फिल्में भी इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर ही बनी थीं। उस दौर में अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। इन फिल्मों के जरिए यह समझ उभरती है कि प्रेस की आजादी, असहमति का अधिकार और सत्ता की आलोचना, लोकतंत्र की मूल शर्तें हैं। जब इन्हें कुचला जाता है तो औपचारिक रूप से लोकतंत्र बरकरार रहते हुए भी उसकी आत्मा मर जाती है।

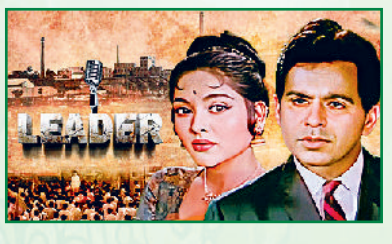

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करती 'रंग दे बसंती': वर्ष 2006 में आई आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' युवाओं को व्यवस्था से सवाल करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने को प्रेरित करती है। फिल्म में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की कथा और समकालीन युवाओं की कहानी समानांतर चलती है। मीडिया ट्रायल, रक्षा घोटाला और अहिंसक-हिंसक प्रतिरोध के बीच झूलते पात्र, दर्शकों से यह सवाल पूछते हैं कि संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध का अधिकार किस हद तक और किस रूप में इस्तेमाल होना चाहिए?

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही अपने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी मिले। कुछ फिल्म मेकर्स ने कई ऐसी फिल्में बनाईं, जिनमें इन लोकतांत्रिक अधिकारों और उनसे जुड़े कई पक्षों की बात की गई है। ऐसी ही कुछ फिल्मों पर एक नजर।

इन हिंदी फिल्मों में सुनाई दी

लोकतांत्रिक अधिकारों की गूंज

सामाजिक न्याय पर आधारित फिल्म-आरक्षण

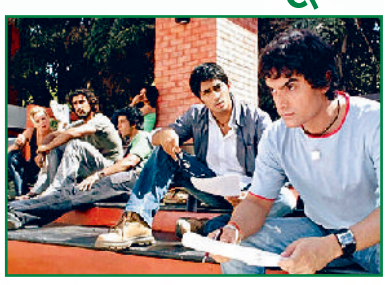
अन्याय के विरुद्ध युवा प्रतिरोध दिखाती-रंग दे बसंती

'स्वदेस' में दिखी गांधीजी के ग्राम स्वराज की झलक: साल 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेस' सीधे किसी अनुच्छेद पर नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना गरिमापूर्ण जीवन, बुनियादी सुविधाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ग्राम स्वराज पर आधारित है। फिल्म का एनआरआई नायक गांव लौटकर बिजली, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए काम करता है। इससे यह संदेश उभरता है कि लोकतंत्र केवल शहरों में नहीं, बल्कि आखिरी नागरिक तक विकास पहुंचाने का वादा है और नागरिक भी इस प्रक्रिया के सहभागी हैं।

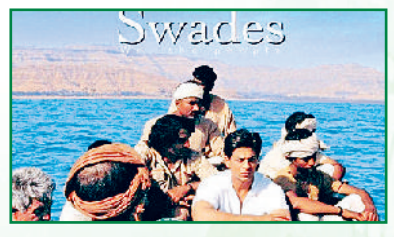

सामाजिक भेदभाव को उजागर करती 'आर्टिकल 15': संविधान का 'अनुच्छेद-15' धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। साल 2019 में रिलीज फिल्म 'आर्टिकल-15' एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो दलित लड़कियों के बलात्कार, हत्या की जांच के बहाने इस भेदभाव की जड़ें दिखाती है। फिल्म दर्शक को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि संवैधानिक शब्दावली 'अनुच्छेद-15' के साथ जोड़कर यह सोचने पर मजबूर करती है कि भेदभावरहित समाज बनाना, केवल राज्य की नहीं, समाज और नागरिक की भी जिम्मेदारी है।

सामाजिक न्याय का संदेश देती 'आरक्षण': वर्ष 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'आरक्षण' सामाजिक न्याय के विषय पर आधारित है। इस फिल्म का कथानक उच्च शिक्षा में आरक्षण नीति के इर्द-गिर्द घूमता है और अनुच्छेद-16 के तहत समान अवसर तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों के नैतिक और राजनीतिक सवालों को उठाता है। फिल्म में एक आदर्शवादी प्रिंसिपल और बाजारवादी शिक्षा मॉडल के बीच संघर्ष भी दिखाया गया है।

अहिंसक प्रतिरोध का महत्व बताती 'सत्याग्रह': संविधान के अनुच्छेद-19 और शांतिपूर्ण विरोध वाले कथानक पर बेस्ड 2013 की फिल्म 'सत्याग्रह' भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन को केंद्र में रखती है और अनुच्छेद-19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा, विरोध और संगठन बनाने के अधिकार को कहानी में रूपांतरित करती है। फिल्म में एक वृद्ध गांधीवादी की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर उतरी भीड़, सोशल मीडिया और युवा नेतृत्व यह दिखाते हैं कि लोकतंत्र में अहिंसक प्रतिरोध सत्ता को जवाबदेह बनाने का वैध तरीका है। *

इसरो की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू

स्थाई स्वदेशी स्पेस स्टेशन निर्माण के लिए बुलाई निविदा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) की आधारशिला रखने की प्रक्रिया तेज कर दी है। योजना के अनुसार, इसका पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जबकि 2035 तक इसे पूरी तरह से वर्किंग स्पेस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने हाल ही में भारतीय कंपनियों से 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (इओआई)' जारी कर बीएएस-01 नामक पहले मॉड्यूल के निर्माण में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है।

यह पहली बार है जब भारत ने अपने स्थाई मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में औपचारिक और ठोस कदम उठाया है। बीएएस के माध्यम से लक्ष्य अंतरिक्ष में लंबे समय तक इंसानी उपस्थिति स्थापित करना है। भारत अब केवल अंतरिक्ष में जाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां रहकर वैज्ञानिक शोध और तकनीकी प्रयोग भी करेगा।

- इसरो कंपनियों को कच्चा माल तकनीकी ड्रॉइंग और थ्री-डी मॉडल देगा
- कंपनियों को किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं

योजना के अनुसार, इसका पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जबकि 2035 तक इसे पूरी तरह से वर्किंग स्पेस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा

अंतरिक्ष में इस तरह दिखेगा स्वदेशी स्पेस स्टेशन

पूरी तरह से स्वदेशी

इस परियोजना की एक खास बात यह है कि यह पूरी तरह भारतीय प्रयास होगा। सरकार की ओर से उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और न ही किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आउटसोर्स करने की अनुमति होगी। इसरो कंपनियों को कच्चा माल, तकनीकी ड्रॉइंग और थ्री-डी मॉडल उपलब्ध कराएगा।

उच्च मानकों का पालन करना होगा

इसरो ने दो पूर्ण सेट मॉड्यूल धरती पर तैयार करने की योजना बनाई है, ताकि परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन के बाद सर्वश्रेष्ठ हार्डवेयर को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। यह कार्य सामान्य निर्माण प्रक्रिया से कहीं अधिक जटिल है। कंपनियों को विशेष वेल्डिंग तकनीकों का विकास करना होगा और उच्च मानकों का पालन करना होगा।

बीएएस-01 नामक मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा

बीएएस-01 मॉड्यूल का स्ट्रक्चर अल्ट्रा मॉडर्न होगा। प्रत्येक मॉड्यूल का व्यास लगभग 3.8 मीटर और ऊंचाई करीब 8 मीटर होगी। इन्हें हाई-पावर्ड एल्यूमिनियम एलॉय (एए-2219) से तैयार किया जाएगा, जो ह्यूमन मिशनों के लिए मान्यता प्राप्त सामग्री है। इसरो ने स्पष्ट किया है कि इन मॉड्यूल्स को वही सुरक्षा और गुणवत्ता मानक पूरे करने होंगे, जो गगनयान मिशन के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री इन्हीं मॉड्यूल्स के भीतर रहकर काम करेंगे।

कई तरह के अनुसंधान हो सकेंगे: *इसरो का मानना है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन देश के वैज्ञानिक और तकनीकी भविष्य में अहम भूमिका निभाएगा। यहां माइक्रोग्रैविटी में दीर्घकालिक प्रयोग किए जा सकेंगे। मानव शरीर पर अंतरिक्ष वातावरण के प्रभावों का अध्ययन होगा और नई तकनीकों का परीक्षण करेंगे।*

भारत चुनिंदा देशों में शामिल होगा

यह उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी, जिन्होंने न केवल अंतरिक्ष में मानव भेजा है, बल्कि वहां स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की क्षमता भी हासिल की है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक नया अध्याय होगा और आने वाले दशकों में देश की वैज्ञानिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक बनेगा।

मिर्जापुर धर्मांतरण केस मास्टरमाइंड इमरान अरेस्ट

मिर्जापुर। यूपी स्थित मिर्जापुर के जिम में दोस्ती कर धर्मान्तरण कराने के मामले में मुख्य आरोपी सरगना इमरान को दिल्ली एयरपोर्ट से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान को शुक्रवार रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूचना पर मिर्जापुर पुलिस शनिवार की सुबह दिल्ली पहुंची।

महाराष्ट्र में जीएसटी अधिकारी की मौत

बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक जीएसटी अधिकारी के मौत के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अधिकारी का शव कार में संदिग्ध स्थिति में बरामद हुआ। मामले में मृतक अधिकारी की पत्नी का कहना है कि दफ्तर में लगातार मानसिक उत्पीड़न और निजी जीवन में मिल रही धमकियों के कारण उनके पति टूटकर आत्महत्या कर ली।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

लखनऊ में शनिवार को यूपी दिवस पर बोले गृहमंत्री अमित शाह

उत्तर प्रदेश को बताया देश की धड़कन- आत्मा 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतरीं

एजेंसी ▶▶ लखनऊ

लखनऊ में शनिवार को यूपी दिवस पर कार्यक्रम हुआ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 3 दिनी कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृहमंत्री शाह पहुंचे

3 दिनी कार्यक्रम के पहले दिन शाह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया

यह श्रीराम, कृष्ण, शिव, बुद्ध की धरती

संबोधन के दौरान गृहमंत्री शाह के साथ सीएम योगी और उपमुख्यमंत्री

राजधानी लखनऊ में शनिवार को यूपी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर चलने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने यहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी का शताब्दी वर्ष होगा। यूपी विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। यूपी भारत की धड़कन और आत्मा है। भारत के विकास का इंजन है, और विकसित भारत का भी इंजन बनेगा। यह श्रीराम, कृष्ण, शिव, बुद्ध की धरती है। प्रेरणा स्थल पर पहली बार आया हूं।

- 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए

यहां तीन महान विभूतियों की मूर्ति लगी है। यह स्थल राष्ट्र की जागृत का स्थल बनेगा। यह दशकों तक देश को दिशा देगा। 65 एकड़ में पहले कूड़े का पहाड़ था। भाजपा सरकार ने कूड़े को कंचन में बदला है। शाह ने 'जय श्री राम' का जयकारा लगाकर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने 'भारत माता की जय' के भी नारे लगाए।

यूपी देश के विकास का इंजन भी बन रहा

लोगों को जोर से शाह के साथ नारे लगाए। मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। योगीजी ने यूपी को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। 15 अगस्त, 2047 को जब देश की आजादी की सदी मनाई जाएगी, तब यूपी विकसित बनेगा। विकसित भारत का अहम राज्य है। यूपी भारत की धड़कन और आत्मा है। देश के विकास का इंजन भी बन रहा है।

5 जिलों को सम्मानित किया

भाजपा सरकार ने कूड़े को कंचन में बदला है। सीएम युवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों को सम्मानित। युवाओं को ऋण देंगे की व्यवस्था, 1.30 लाख युवाओं को करोड़ों का ऋण दिया है। शुभांशु शुक्ला, अलख पांडेय, सुधांशु सिंह, रश्मि आर्य को सम्मान। हरिओम पंवार को भी सम्मानित करने का मौका मिला है। लंबे समय से सुनता आया हूं।

ओडीपीओ से वैश्विक पहचान मिलेगी

शाह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में 'एक जनपद-एक व्यंजन' योजना की शुरुआत की। इसका मकसद राज्य के 'एक जिला-एक उत्पाद' कार्यक्रम की तर्ज पर हर जिले के पारंपरिक खाने-पीने की खास चीजों को एक अलग पहचान देना है। ओडीओसी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की है। शाह ने विधानसभा चुनाव की बात करते हुए कहा कि मैं 2017 को याद करूंगा।

सरदार पटेल योजना की शुरुआत भी की

शाह ने सरदार पटेल योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह 10 खराब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में काफी उपयोगी होगी। यूपी का हर जिला रोजगारयुक्त होगा। देशभर में जाने वाले को यूपी में रोजगार की व्यवस्था होगी। अपने माता-पिता की सेवा करें।

परिवारवादी पार्टियां कल्याण नहीं कर सकतीं

शाह ने कहा कि अगला साल चुनाव का साल है। यूपी के विकास के लिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। परिवारवादी पार्टियां यूपी का कल्याण नहीं कर सकती हैं। भाजपा ही कर सकती है। मोदी, योगी ने विकास का सर्वश्रेष्ठ दिया है। डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेववे, हाईवे दिए। भ्रष्टाचार समाप्त किया। गरीब के लिए योजनाएं आईं।

योजनाओं से कृषि विकास दरे बढ़ेगी

शाह ने कहा पीएम के नेतृत्व में सीएम योगी ने योजनाओं को जमीन पर उतारा। कांग्रेस, सपा, बसपा ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाया है।

एनसीपी की दोनों जगह भूमिका अहम

अकोला-सांगली में भाजपा बहुमत से चूकी, शरद पर 'टिकी' निगाहें

एजेंसी ▶▶ अंकोला

महाराष्ट्र की नगर राजनीति में नया समीकरण उभर आया है। सांगली और अकोला नगर निगमों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से चूक गई है। ऐसे में एनसीपी (एसपी) दोनों निकायों में निर्णायक भूमिका में है। 3-3 पार्षदों के साथ यह सत्ता गठन की दिशा तय करने वाला बन गया है। 78 सदस्यीय सांगली-मिरज-कुपवाड़ में भाजपा को 39 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए 40 की जरूरत है। कांग्रेस को 18, अजित को 16, शिंदे को 2 सीटें मिलीं हैं। और एनसीपी (एसपी) को 3सीटें मिली हैं। भाजपा बहुमत से एक कदम दूर रह गई। समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है।

समर्थन को लेकर बातचीत तेज हो गई

दोनों नगर निगमों में सत्ता गठन के लिए तेज राजनीतिक बातचीत चल रही है। भाजपा को बहुमत के लिए या तो छोटे दलों का साथ चाहिए या निर्दलीयों का समर्थन। इस बीच खबरें हैं कि एनसीपी (एसपी) के पार्षद भाजपा के संपर्क में हैं।

फिल्म निर्माता विक्रम और बेटी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मुंबई। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। विक्रम भट्ट और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पिता-पुत्री पर एक कारोबारी ने 13.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने कारोबारी से फिल्म और अन्य बिजनेस में इन्वेस्ट करने पर भारी लाभ का वादा करके रकम ली थी। मामला दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। व्यापारी ने भट्ट द्वारा किए गए वादे के बाद लाभ न मिलने पर पुलिस में शिकायत की। व्यापारी ने कहा कि विक्रम और कृष्णा ने उन्हें भारी मुनाफे का आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए।

राशिफल

मेष — किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के सानिध्य मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

वृष — व्यर्थ के क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। किसी मित्र से वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है।

मिथुन — आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती है। परिश्रम भी अधिक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

कर्क — आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा, परन्तु बातचीत में सन्तुलित रहें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तरक्की भी हो सकती है। आय बढ़ेगी।

सिंह — आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परन्तु धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या — मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें।

तुला — आत्मविश्वास में कमी रहेगी। बातचीत में सन्तुलन बनाये रखें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग-दौड़ अधिक रहेगी।

वृश्चिक — आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

धनु — आत्मविश्वास से लबरेज रहेगें। परन्तु अति उत्साही होने से बचें। संयत रहें। माता का साथ मिलेगा। आय भी बढ़ेगी। संतान को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं।

मकर — माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। तरक्की के योग बन रहे हैं।

कुंभ — अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परन्तु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। भाइयों का सहयोग रहेगा।

मीन — शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा।

भागवत रांची में आदिवासी समूहों से बातचीत करेंगे

रांची (भाषा) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को रांची में विभिन्न आदिवासी समूहों के साथ बंद कमरे में संवाद करेंगे। झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर आए भागवत ने शुक्रवार को आरएसएस के प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात की थी। संगठन के एक पदाधिकारी ने कहा, "वह विभिन्न आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरे में 'जनजातीय संवाद' नामक बैठक करेंगे। कार्यक्रम में आरएसएस नेताओं सहित करीब 500 लोग मौजूद रहेंगे।" उन्होंने बताया कि पांच घंटे का यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 10.30 बजे शुरू होगा। भागवत के शाम को पटना रवाना होने का कार्यक्रम है।

तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण न पढ़कर अपने पद का अपमान किया: स्टालिन

चेन्नई (भाषा)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्यपाल आर. एन. रवि ने विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण न पढ़कर अपने पद का "अपमान" किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "पहले के राज्यपाल आर. एन. रवि जैसे नहीं थे और मुझे उनकी आलोचना करने पर विवश होना पड़ रहा है।" स्टालिन ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में कहा, /"मैं ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा हूं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों सी. एन. अन्नादुरई, एम. करुणानिधि, एम. जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता के कार्यकाल में नहीं देखी गईं...राज्यपाल (रवि) विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण न पढ़कर और सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने पर जोर देकर अपने पद का अपमान कर रहे हैं।/" राज्यपाल आर. एन. रवि ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा तैयार परंपरागत अभिभाषण देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अभिभाषण के पाठ में /"असत्य/" या /"गलतियां/" हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु ने भाषण का तमिल संस्करण पढ़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा में हमेशा राज्यपाल के अभिभाषण के समापन पर राष्ट्रगान बजाया जाता है और सत्र की शुरुआत में तमिल थाई वजथु (तमिल माता की स्तुति) बजाया जाता था। स्टालिन ने कहा कि देशभक्ति में हम किसी से कम नहीं हैं और किसी को जरूरत नहीं है कि वह हमें इसके बारे में समझाए। चुनौतियों का सामना करना मेरे लिए कोई नयी बात नहीं है और मैंने कई चुनौतियों को पार किया है।/" राज्य में अपराध के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शासन में आपराधिक घटनाएं पहले के ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) शासन की तुलना में कम हैं।

गणतंत्र दिवस पर दिखेगा 'ऑपरेशन सिंदूर'

नई दिल्ली। इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ खास दिखाई देगा। इसमें सेना का शौर्य 'ऑपरेशन सिंदूर' दिखाई देगा।

शब्द पहेली - 6119

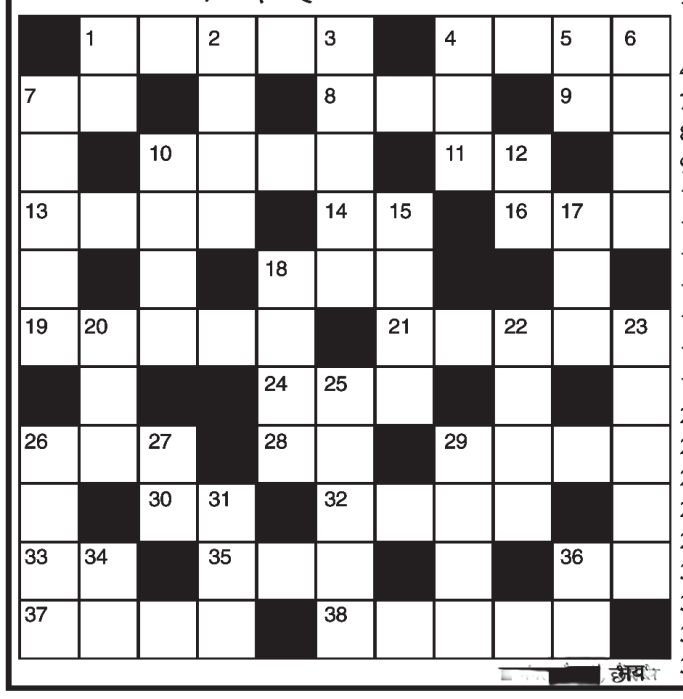

बाएँ से दाएँ

1. फिल्म 'बॉबी' के निर्माता-निर्देशक -2,3
4. आश्चर्य, विलक्षणता-4
7. जीत, फतेह-2
8. आकाश रेखा, छोर-3
9. तल, पैंदा-2
10. थाती, धरोहर-4
11. मोटा आटा-2
13. सलाह, मशवरा-4
14. अन्य, वो, तिन-2
16. घर,गृह-3
18. धावक (अंग्रेजी-3)
19. नाम रखना-2,3
21. परामर्शदाता-5
24. सुनसान, नीरव-3
26. वन, जंगल-3
28. मिट्टी, रेत-2
29. चेतनाहीन-4
30. पराग कण-2
32. भयभीत होना-4
33. छोटी सवारी गाड़ी-2
35. फूलों का हार जो बालों में लगाते हैं,वेणी-3
36. द्वार,किवाड़-2
37. जनता की राय-4
38. नाटक लिखने वाला-5

ऊपर से नीचे

1. मत, सलाह-2
2. करतब-4
3. वह जंगल जो संरक्षित हो-3,2
4. अनश्वर, चिरयुवा-3
5. लीन, मग्न-2
6. जलाऊ लकड़ी-4
7. रनिवास 3,2
10. मूर्ख (उर्दू-4)
12. बांया-2
15. आनंदित होना-4
17. शत्रुघ्न सिन्हा व रीना राय की फिल्म-3
18. योद्धा-4
20. अमिताभ के तिहरे रोल वाली फिल्म-3
22. मुआवजा-4
23. चित्रपट, फिल्मी दुनिया-3,2
25. राज वंश-2,3
26. काम, कार्य-4
27. मादा का विलोम-2
29. उपद्रव फैलाने वाला-4
31. दुनिया, जहान-3
34. क्रिकेट में बनते हैं-2
36. पंख, पराया-2

शब्द पहेली- 6118 का हल

अ	रा	ज	क	ता			म	वा	ली	
स	म		ल		चा	ला	न		ख	त
मा			प	ना	ह		न			म
न	ज	र	ना			म		क	या	स
ता		व		ना	ला	य	क		प	
	प्रा	ण		म		खा		जा	न	
	रु		आ	ज	मा	ना		हि		म
स	प	ना		द			ब	ल	वा	न
र			स		ल	की	र			भा
ल	व		न	सी	ब		सा		दा	व
	ध	म	की			इ	त	मी	ना	न

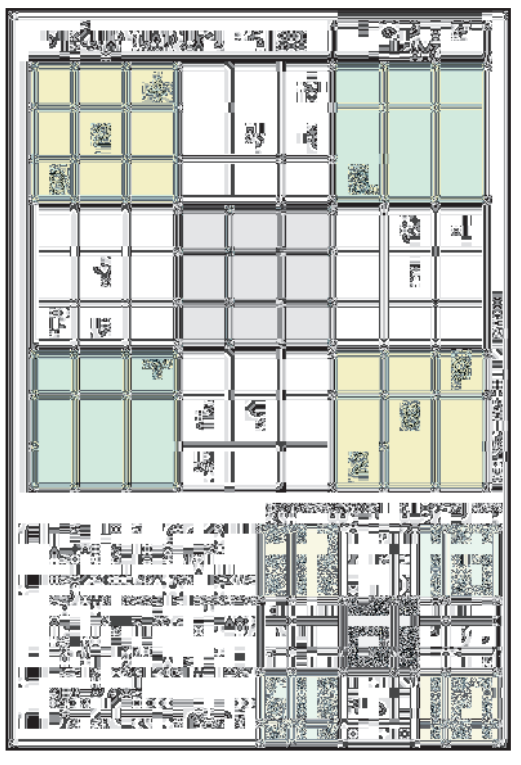

खबर संक्षेप

सरहिंद में रेलवे की आउटर लाइन पर ब्लास्ट

सरहिंद। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में रेल लाइन पर धमाका हुआ है। शुक्रवार रात करीब नौ बजे

सरहिंद रेलवे स्टेशन की एक आउटर लाइन पर इंजन के गुजरने के दौरान धमाका हुआ। रात करीब 11 बजे इसकी सूचना राजकीय रेलवे पुलिस को दी गई। हमले में एक लोको पायलट के घायल होने की भी सूचना है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है।

कांग्रेस को बड़ा झटका सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी

लखनऊ। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी के सभी पदों के साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उनके पार्टी छोड़ने की वजह फिलहाल साफ नहीं है लेकिन वे पार्ट से नाराज चल रहे थे। इस बीच अटकलों का बाजार गर्म है। वे फिर से बीएसपी का दामन थाम सकते हैं।

कांग्रेस को 'शांति बोर्ड' बनाने की जरूरत

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस की राज्य इकाइयों में कथित "आंतरिक कलह" को लेकर तंज कसते हुए शनिवार को कहा कि पार्टी को अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए एक "शांति बोर्ड" बनाने की जरूरत है। भाजपा ने कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस की झारखंड इकाई के भीतर भी "आंतरिक मतभेद" की खबरों का हवाला दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 'एक्स' पर एक पोस्ट की।

प्रधानमंत्री के भाई के घर तैनात पुलिसकर्मी को जेल

अहमदाबाद। यहां की एक मजिस्ट्रियल कोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल को गुजरात निषेध

अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। वह 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमभाई मोदी के आवास पर सुरक्षा ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाया गया था। लक्ष्मणसिंह परमार को 1साल के साधारण कारावास दी है।

हैदराबाद : इमारत में लगी आग, पांच लोगों के फंसे

हैदराबाद (भाषा)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में शनिवार को चार मंजिला एक इमारत में भीषण आग लगने से पांच लोगों के वहां फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिस इमारत में आग लगी है, उसमें फर्नीचर और अन्य सामान की दुकानें हैं। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी सी सज्जनार ने बताया कि दमकल कर्मियों, पुलिस, वृहद हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और अन्य एजेंसियों के कर्मी बचाव अभियान को अंजाम दे रहे हैं।

बंबई हाईकोर्ट की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में बोले-सीजेआई

उच्च न्यायालय 'प्राथमिक प्रहरी' उन्हें अधिक सक्रिय होना चाहिए

एजेंसी ▶▶ मुंबई

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि उच्च न्यायालयों को कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं को लेकर अधिक सतर्क और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता और सुलह के तंत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधान न्यायाधीश ने यहां दो कार्यक्रमों में अपने विचार रखे। उन्होंने फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में बोलने के बाद बंबई उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में अपने संबोधन में प्रधान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों से कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं को लेकर अधिक सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अपने दरवाजे पर दस्तक दिए जाने का इंतजार न करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "न्याय की सुलभता को राज्य की ओर से गारंटीकृत सेवा के स्वतः प्रदत्त अधिकार (पैसिव राइट) में बदलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है।"

बार चुनावः एससी-एसटी अधिवक्ताओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनावों में एससी- एसटी अधिवक्ताओं के लिए सीटें आरक्षित करने के निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने जोर दिया कि एसे आरक्षण को न्यायालय द्वारा जारी परमादेश के बजाए विधायी संशोधन से ही लागू किया जा सकता है। पीठ ने मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। सीजेआई की पीठ ने पेशेवर निकायों के भीतर सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को रेखांकित किया। यह फैसला यूनिवर्सल डॉ. आंबेडकर एडवोकेट्स एसो द्वारा दायर रिट के जवाब में आया।

छत्तीसगढ़ में रातों-रात चोरी 10 टन वजनी स्टील का पुल

1. 70 फुट लंबा 05 फुट चौड़ा 40 साल पुराना
2. गैस कटर से काटकर कबाड़ के रूप में बेचा
3. 15 लोगों ने की वारदात, पांच आरोपी पकड़े
4. 7 टन स्टील को नहर में ही छिपा दिया था

बंगाल में जारी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर अर्थशास्त्री ने जताई चिंता

एसआईआर जल्दबाजी में, लोकतांत्रिक भागीदारी पर हो सकता खतरा: अमर्त्य सेन

■ समय का दबाव चुनाव अधिकारियों पर दिख रहा

एजेंसी ▶▶ कोलकाता

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर गहरी चिंता जताई और चेतावनी दी कि यह कवायद 'अनावश्यक जल्दबाजी' में की जा रही है और कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह लोकतांत्रिक भागीदारी को खतरे में डाल सकती है। सेन (92) ने बोस्टन से दिए साक्षात्कार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लोकतांत्रिक महत्व पर विचार करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया तभी मताधिकारों को मजबूत कर सकती है, जब इसे सावधानी के साथ और पर्याप्त समय लेकर अंजाम दिया जाए। बंगाल के मामले में ये दोनों शर्तें "नदारद" हैं। मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अगर सावधानी से और पर्याप्त समय लेकर किया जाए तो यह एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस समय बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। एसआईआर कवायद जल्दबाजी में की जा रही है और मताधिकार रखने वाले लोगों को आने वाले विस चुनावों के लिए अधिकार को साबित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है।

अर्थशास्त्री को सुनवाई के लिए किया था तलब

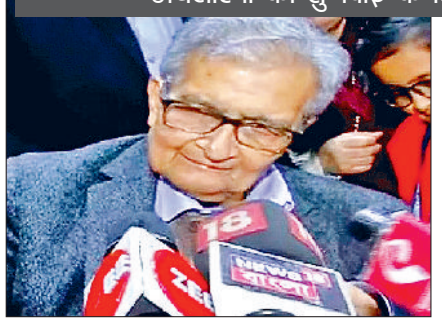

अर्थशास्त्री ने कहा कि मतदाता सूची में उनके और उनकी मां अमिता सेन की उम्र के अंतर को लेकर आयोग द्वारा "तार्किक विसंगति" पाए जाने के बाद 90-वर्षीय सेन को सुनवाई के लिए तलब किया गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या एसआईआर से किसी राजनीतिक दल को लाभ हो सकता है, सेन ने कहा कि वह इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते।

चुनाव आयोग पर निशाना

विसंगतियों वाले वोटरों की सूची जारी करने में अनिश्चितता बनी

कोलकाता (भाषा)। निर्वाचन आयोग को आंकड़ों में विसंगतियों वाले मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करने में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बीएलओ को समय पर सॉफ्टवेयर प्राप्त नहीं हुआ है। सुको ने 19 जनवरी को आयोग को सूची में शामिल लोगों और अनमैप्ड मतदाताओं के नाम पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था।

सपा अध्यक्ष का आरोप

एसआईआर में अनियमितताएं बरती जा रहीः अखिलेश यादव

लखनऊ (भाषा)। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर शनिवार को सवाल उठाए और अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का रक्षक नहीं, 'वोट चोरी' की साज़िश का सहभागी बना

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मुख्य विपक्षी दल समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का दावा किया और आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं, बल्कि इस 'वोट चोरी' की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि एसआईआर को एक व्यक्ति, एक वोट के संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करने के हथियार में बदल दिया गया है, ताकि भाजपा तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर गुजरात कांग्रेस कमेटी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए दावा किया कि गुजरात में एसआईआर के नाम पर सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, जहां-जहां एसआईआर, वहां-वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है। वह किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है - यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। उन्होंने दावा किया कि सबसे चौंकाने वाली और ख़तरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों-हजार आपत्तियाँ दर्ज की गईं। राहुल गांधी ने कहा, रचुन-चुनकर ख़ास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां भाजपा को हार दिखती है, वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। यही चलन आलंद में दिखा। यही राजुरा में हुआ। और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है, जहां एसआईआर थोपा गया है।

■ राहुल गांधी का गुजरात को लेकर किया दावा

सीएम ममता ने जताया कड़ा विरोध

बंगाली उपनामों को लेकर छिड़ा विवाद

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बंगाल की संस्कृति और पहचान को कमतर आंकने की कोशिश है।मैं अंग्रेजी में 'ममता बनर्जी' लिखती हूं और बांग्ला में 'ममता बंद्योपाध्याय'। इसमें क्या समस्या है? मामला सदियों पुराने बंगाली उपनामों के छोटे और बड़े रूपों के बीच अंतर का है। आयोग का सॉफ्टवेयर उन लोगों पर सवाल उठा रहा है, जिनके उपनाम बदले हैं। पिछली पीढ़ियों की तुलना में बदल गए हैं। सॉफ्टवेयर इसे 'बेमेल उपनाम' मानकर नोटिस जारी कर रहा है। कोलकाता के हाजरा इलाके के निवासी स्पंदन भट्टाचार्जी जैसे कई मतदाता इसे लेकर परेशान हैं। उन्हें 29 जनवरी को सुनवाई के लिए बुलाया गया है क्योंकि उनके पिता का नाम 2002 की सूची में 'अशोक भट्टाचार्य' दर्ज है।

रॉबर्ट वाड्रा के केस में ईडी को फटकार

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट के मामले में राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने ईडी को ही झटका दे दिया है। कोर्ट ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की सूची दाखिल न करने पर ईडी को फटकार लगाई है। दरअसल, अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर पूरक आरोपपत्र पर बहस करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को समय दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े एक मामले में वाड्रा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

दस्तावेज दाखिल न करने पर कोर्ट भड़की

यह है मामला : संजय भंडारी से जुड़े मामले में ईडी ने पहले भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। भंडारी की प्रत्यर्पण याचिका ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दी थी। जुलाई 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। ईडी ने आयकर विभाग की आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

फरवरी में सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि ईडी को दस्तावेजों को दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अब इस मामले की अगल सुनवाई 26 फरवरी 2026 को होगी। वाड्रा पर जमीन सौदे में कथित अनियमितता से जुड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है।

तिरुवनंतपुरम नगर-निगम ने भाजपा पर लगाया जुर्माना

तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) पर 19.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे के दौरान शहर में फुटपाथों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाने पर लगाया गया है। बोर्ड लगाने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सचिव की शिकायत के बाद कैंटोनमेंट पुलिस ने शुक्रवार देर रात भाजपा जिला अध्यक्ष करमना जयन के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिसंबर में हुए नगर निगम चुनाव में तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने 50 सीटें जीती थीं। इसके बाद 26 दिसंबर को भाजपा के वीवी राजेश को यहां का मेयर बनाया गया था।

भाजपा का ही है यहां मेयर

केरल हाइकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का आरोप

एफआईआर में केरल हाई कोर्ट के कई आदेशों और स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन का आरोप है। इसमें कहा गया कि भाजपा जिला समिति ने प्रधानमंत्री के दौरे के हिस्से के रूप में फुटपाथों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाए। इससे पालियम जंक्शन से पुलिमूड्ड जंक्शन तक जनता को असुविधा हुई। बीएनएस की धारा 223 और 285 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(बी) के तहत दर्ज किया गया है।

भोजशाला में शांति के बाद...वर्दी पर आया 'बसंत'

सभी पुलिसवालों ने डीजे पर किया डांस

धार। धार में शुक्रवार को बसंत पंचमी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यहां भोजशाला में जहां पूजा-पाठ होती रही, वहीं कमाल मौला मस्जिद में नमाज भी पढ़ी गई। सफलतापूर्वक आयोजन के बाद शनिवार को पुलिस कर्मचारियों ने जश्न मनाया। सभी ने डीजे पर डांस किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। यह आयोजन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी।

सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा होगी

28 को राष्ट्रपति का अभिभाषण

बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

बजट सत्र से पहले सरकार ने सियासी सहमति बनाने की कवायद तेज कर दी है। संसद के आगामी बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

इस बैठक में विधायी कार्यसूची और सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य सत्र को सुचारु रूप से चलाना और सभी दलों की राय जानना है। बजट सत्र की शुरुआत

28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में अभिभाषण से होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 27 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी। इस बैठक में सरकार और विपक्ष सत्र के एजेंडे पर अपनी-अपनी बात रखेंगे। इस बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो रविवार है। यह संसद के इतिहास में एक दुर्लभ अवसर माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवां बजट पेश करेंगी।

बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज मथुरा और वृंदावन का दौरा करेंगे

लखनऊ (भाषा)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नवीन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम भी सुनेंगे। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने यहां जारी एक बयान में बताया कि नवीन वृंदावन के अक्षय पात्र चंद्रोदय मंदिर में रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का 130वां संस्करण सुनेंगे। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहेंगे।

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी ने 4 महीने का सूखा किया खत्म

5 हाईवे समेत 563 सड़कें बंद, गांवों में ब्लैकआउट

एजेंसी ▶▶ शिमला

हिमाचल प्रदेश में 4 महीने से जारी सूखे का दौर भारी बर्फबारी और बारिश के साथ खत्म हो गया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाके बर्फ से लकदक हो गए। पहाड़ों की रानी शिमला, मनाली, डलहौजी और चायल जैसे पर्यटन स्थलों में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। भारी बर्फबारी-बारिश से 5नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में 563 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश के कई इलाके कट गए हैं। प्रदेश में 10,384 ट्रांसफार्मर ठप होने से सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है।

बारिश के साथ ओले भी गिरे

शिमला, मनाली, डलहौजी और चायल में सीजन का पहला हिमपात

148 को किया गया रेस्क्यू, पर्यटक फंसे

शिमला मे बर्फबारी के बीच पर्यटक

कुफरी-फागू से 100 और आनी के रघुपुरगढ़ से 48 को किया रेस्क्यू किया गया है। बारिश-बर्फबारी से फसलों को संजीवनी के साथ पर्यटन को भी पंख लगने की उम्मीद है। शिमला-मनाली में पर्यटकों ने मस्ती की। उधर, मनाली और बंजार उपमंडल के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। मनाली विंटर कार्निवल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।

बर्फीला तूफान भी चला आवागमन ठप

शिमला, लाहौल-स्पीति में बर्फीला तूफान भी चला। तूफान के बीच पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सैकड़ों पर्यटक वाहन बर्फ में घंटों फंसे रहे। आनी-कुल्लू, शिमला-किन्नौर, मनाली-लेह, हाटकोटी-पांवटा साहिब व चंबा-भरमौर एनएच समेत सैकड़ों सड़कें बंद होने से परिवहन सेवाएं भी ठप हो गई है।

कई शहरों से उड़ानें रद्द रहीं

शुक्रवार को कांगड़ा, कुल्लू और शिमला हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द रहीं। कालका-शिमला ट्रेक पर पेड़ गिरने से 3-4 घंटे तक ट्रेनें बाधित रहीं। चौहार घाटी व छोटा भंगाल के सभी गांवों में दो से 20 सेमी तक बर्फबारी रिकार्ड की गई है। चंबा में शुक्रवार को एक से डेढ़ फीट और निचले क्षेत्रों में 25.4 सेमी हिमपात हुआ। तेज हवाएं चलने से भरमौर की गाण, सुनारा और छतराड़ी पंचायतों में 12 मकानों की छतें उड़ गईं। लाहौल का संपर्क कुल्लू से कट गया है।

अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में घुसने की कोशिश धक्का-मुक्की, सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगे

एजेंसी ▶▶ प्रयागराज

प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी है। शनिवार रात कुछ युवकों ने शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश की। वे योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से युवकों की धक्का-मुक्की हो गई। इससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने शंकराचार्य की जान को खतरा बताया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के साथ ही बसंत पंचमी पर भी विरोध स्वरूप स्नान नहीं किया। वह एक हफ्ते से अपने शिविर में भी नहीं गए हैं। अब उनके शिष्यों ने अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जता दी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकराचार्य जी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए शिविर के चारों ओर 10 हाई-डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

शिष्यों का दावा- शंकराचार्य की जान को खतरा

प्रयागराज माघ मेला में प्रशासन द्वारा स्नान से रोकने पर धरने पर बैठे हैं शंकराचार्य

माघ मेला प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल

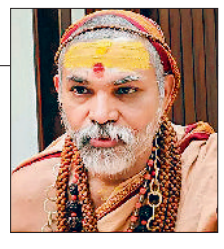

मीडिया प्रभारी योगिराज ने केवल बाहरी तत्वों ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, 'प्रशासन की तरफ से रात के अंधेरे में आकर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। ऐसे में हमें डर है कि प्रशासन कब क्या कर दे और क्या (संदिग्ध वस्तु) रखवाकर फंसाने का काम कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और विरोध करने पर शिष्यों से मारपीट की।

भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को अंगीकृत कर गणतंत्र का मार्ग चुना था। इन 77 वर्षों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में अपार प्रगति की है। उसने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया, सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे प्रगतिशील और समावेशी संविधानों में गिना जाता है। सदियों से चली आ रही लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से, संविधान ने महिलाओं को समानता, गरिमा और सशक्तिकरण का आधार प्रदान किया है। वैश्विक परिदृश्य में आज जब दुनिया के अधिकांश छोटे-बड़े देशों में सत्ता व शासन प्रणाली को लेकर जन असंतोष व उथल-पुथल देखने को मिल रही है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारतीय गणतंत्र अपनी उत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्था की मजबूत बुनियाद पर शान से परचम लहराता हुआ दिख रहा है। अपनी तमाम खूबियों के साथ इसकी प्रासंगिकता आज भी यथावत बनी हुई है। इसके बावजूद स्वस्थ गणतंत्र में राजनीतिक शुचिता से जुड़े सवाल भी खड़े होते हैं। इसके बावजूद कुछ तो ऐसा है कि जो आज भी हमारे लोकतंत्र को कायम रखे हुए है। इसमें गहरी मजबूती और अनगिनत ताकतें हैं। इसी का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

गणतंत्र में राजनीतिक शुचिता से जुड़े सवाल

विश्लेषण

मनीष कुमार चौधरी

स्वतंत्र पत्रकार

जब देश 26 जनवरी, 2026 को एक और गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, गणतंत्र की सेहत पर कुछ गंभीर विचार-विमर्श समय की जरूरत है। ऐसे समय में जब हमारे संवैधानिक ढांचे की नींव बनाने वाली संस्थाओं और विचारों का गहन आकलन हो रहा है, इस पर विचार करना जरूरी है कि 'हम, भारत के लोग', जिन्होंने भारत का पवित्र संविधान बनाया, अपनाया और खुद को दिया, अब इसे किस रूप में देखते-स्वीकारते हैं। ऐसे समय में जब राजनीतिक चर्चा रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर पहलू में घुस गई है, सच्ची राजनीतिक लीडरशिप दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सबसे दुर्लभ संसाधनों में से एक बन गई है। यह निजी हितों को साधने का माध्यम बन गई है, जबकि लीडर की सत्ता जनता के कंधों पर सवार होकर आती है। भूटान के पांचवें और वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 2008 के राज्याभिषेक में शासन की नींव रखते हुए जो नैतिक घोषणा की, यदि उसे हर देश का शासक अपने जीवन में उतार ले तो किसी भी डूबते लोकतंत्र को संजीवनी मिल सकती है।

देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। गणतंत्र की सेहत पर कुछ गंभीर विचार-विमर्श समय की जरूरत है। ऐसे समय में जब संवैधानिक ढांचे की नींव बनाने वाली संस्थाओं और विचारों का गहन आकलन हो रहा है, इस पर विचार करना जरूरी है कि 'हम, भारत के लोग', जिन्होंने भारत का पवित्र संविधान बनाया, अपनाया और खुद को दिया, अब इसे किस रूप में देखते-स्वीकारते हैं। ऐसे समय में जब राजनीतिक चर्चा रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में घुस गई है, सच्ची राजनीतिक लीडरशिप दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सबसे दुर्लभ संसाधनों में से एक बन गई है।

सुशासन की भावना पनपे

भूटान के राजा ने अपने नैतिक भाषण में कहा था- 'अपने पूरे शासनकाल में मैं आप पर राजा की तरह शासन नहीं करूंगा। मैं आपकी रक्षा एक माता-पिता की तरह, देखभाल एक भाई की तरह और सेवा एक बेटे की तरह करूंगा। मैं हमेशा दया, न्याय और समानता की भावना से दिन-रात आपकी सेवा करूंगा।' लेकिन इन बातों के उलट जैसे ही कोई भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करता है तो यह सवाल उठता है कि कितने राजनीतिक नेता सच में ऐसे आदर्शों को मानते हैं? सिद्धांत रूप में ज्यादातर नेता इन मूल्यों के प्रति निष्ठा जताते हैं; व्यवहार में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तर्क दिया जा सकता है कि हमारे जैसे विशाल और विविध देश के लिए क्या ऐसा संभव है? भूटान के राजा की बातों को एक सैद्धांतिक कल्पना बताकर खारिज भी किया जा सकता है। फिर भी, सच्चाई यह है कि सुशासन की भावना की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। सीमित संसाधनों वाले एक छोटे देश का सर्वोच्च नेतृत्व ऐसे आदर्शों में विश्वास कर सकता है और उसे फलीभूत करने का प्रयास कर सकता है तो हमारा देश दूरदर्शी नेतृत्व में क्यों पीछे रहे। खासकर तब हमारे देश में ज्यादा क्षमताएं, अवसर और रणनीतिक फायदे हैं?

बदल रही हैं प्राथमिकताएं

राजनीतिक दल- जो नागरिकों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं- ने अब तक सिर्फ चुनाव जीतने को प्राथमिकता दी है, जनता के दुख-दर्द दूर करना उनकी प्राथमिकताओं से लोप होते जा रहे हैं। चूंकि विधायिका की गुणवत्ता एक स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टियों में बेईमान उम्मीदवारों को टिकट देने से मना करने का साहस होगा, चाहे वे कितने भी चुने जाने योग्य क्यों न दिखें। वे इसके बजाय ऐसे लोगों को मैदान में उतारें जो ईमानदारी का प्रतीक हों और सार्वजनिक जीवन में नए दृष्टिकोण लाएं। हमें अपने भीतर भी झांकना होगा कि क्या हम आम नागरिक के रूप में एक बीमार चुनावी राजनीति में भी उतने ही शामिल हैं जितने राजनीतिक दल। यदि हम यथास्थिति को स्वीकार करने की हद तक गिर जाते हैं तो गणतंत्र को भी बिखरने से रोक नहीं पाएंगे। हर चुनाव में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पार्टियां जीतती हैं, लेकिन लोग हारते हैं। जड़ें जमाए भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण के कई रूप, गहरी सामाजिक-आर्थिक समानताओं की डोर और मजबूत क्यों होती जाती है। ये सवाल जस के तस रह जाते हैं कि चुनावी घोषणापत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते।

तुष्टीकरण की राजनीति

पार्टियों के लिए बड़े-बड़े वादे करना आसान होता है, बार-बार दोहराए जाने वाले वादे फिर-फिर दोहराने का क्रम क्यों जारी रहता है। कोई भी सरकार शासन संभाले, पुरानी बीमारियां फिर से सामने आ जाती हैं। सत्ता का दुरुपयोग, औसत दर्जे का प्रदर्शन, भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण अक्सर नए रूपों, डिजाइनों और रणनीतियों में फिर से पेश किया जाने लगता है। एक राजनीतिक विडंबना यह है कि वही पार्टी जब सत्ता में होती है तो लोकतंत्र को विजयी घोषित करती है; जब विपक्ष में होती है, तो इसे खतरे में बताती है। स्पष्ट है, नैतिक और अनैतिक के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है। लोकलुभावनवाद की राजनीति को ही लें। यह सिर्फ वोट पाने के जरिए के रूप में क्यों इस्तेमाल की जाने लगी है। लंबे समय के विकास और वित्तीय स्थिरता की कीमत पर इसे क्यों नहीं अपनाया जाता? यह जानते हुए कि लोकलुभावन वादों की संस्कृति कार्य-संस्कृति को पंगु बनाती है। देश की जनता को बगैर कर्मठ बनाए बैठे-बिठाए बांटना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। यह नीति राज्यों की अर्थव्यवस्था को इस हद तक प्रभावित कर रही है कि विकास की योजनाएं धन के लिए तरसने लगी हैं। तात्कालिक लाभ के फेर में लगातार, बड़े पैमाने पर विकास को दांव पर लगाया जा रहा है। योग्य और ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाने वाला खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। होते-होते वे इसे अधिकार मानने लगते हैं। कोई भी पार्टी इस सिंड्रोम से पूरी तरह से अछूती नहीं है। राजनीति के दो आम लक्षण राजनीतिक फंडिंग की अपारदर्शी प्रणालियां और भ्रम वाले अभियान जगह-जगह नजर आने लगे हैं। चुनावों में पैसे का प्रभाव अक्सर संदिग्ध वित्तीय ढांचों और गुप्त राजनीतिक गठजोड़ों में निहित होता है। उतना ही चिंताजनक एक भोला-भाला मतदाता वर्ग है, जिसे अक्सर राजनेता आधे-अधूरे सच, भावनात्मक अपीलों और झूठे वादों से धोखा देते हैं।

लोकतांत्रिक मूल्य बनाए रखें

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सदस्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें और उन्हें आगे बढ़ाएं। लोकतांत्रिक सुधार का काम सरकारों, राजनीतिक पार्टियों या सिस्टम पर छोड़ देते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राजनीतिक शुचिता में कमी के बावजूद कुछ तो ऐसा है कि जो आज भी हमारे लोकतंत्र को जिलाए है। इसमें गहरी मजबूती और अनगिनत ताकतें हैं, और यह अभी भी अपनी जगह वापस पा सकता है।

ऐसे दौर में जहां दुष्प्रचार हैरान करने वाली तेजी से सच्चाई को बिगाड़ सकते हैं, एक सशक्त राजनीतिक संस्कृति सिर्फ वांछनीय ही नहीं, जरूरी भी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक शक्ति से हमें इतनी शक्ति तो मिलती ही है कि हम ऐसा कर सकें।

चुनौती के बावजूद हासिल की बड़ी उपलब्धियां

गणतंत्र

रवि शंकर

वरिष्ठ पत्रकार

भारत देश में गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय उत्सव ही नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं, संविधान और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को अंगीकृत कर गणतंत्र का मार्ग चुना था। इन 77 वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपार प्रगति की है। उसने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया, सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

ये 77 वर्ष केवल समय का मापदंड नहीं, बल्कि उस यात्रा का प्रतिबिंब है जिसमें भारत ने चुनौतियों का सामना करते हुए विकास की राह बनाई है। इस दौरान लोगों ने राजनीतिक बदलाव देखे, वहीं विकास की ओर अग्रसर योजनाएं और कार्यक्रम भी देखे। युद्ध से दो चार होना पड़ा तो अपनी परमाणु शक्ति में भी भारत ने इजाफा किया। मेट्रो ट्रेन से लेकर कम्प्यूटर तक भारतीय नागरिकों के जीवन का हिस्सा बने। इतना ही नहीं, भारत ने बैलगाड़ी से लेकर एयर इंडिया तक का सफर तय किया है। नए-नए आविष्कारों और तकनीकी विकास से भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। यह अनायास नहीं है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। बीते 77 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने ऐसा कुछ जरूर हासिल किया है, जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। देश के पास गर्व करने के लिए उपलब्धियां हैं तो अफसोस जताने के लिए वजहें भी हैं। हमें आजादी तो मिल गई ,लेकिन वह आजादी आज किस रूप में है। हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं ने आजाद भारत का जो सपना देखा था, उनकी नजरों में आजादी के जो मायने थे, क्या उसके अनुरूप हम आगे बढ़े हैं। संविधान में एक आदर्श देश की जो परिकल्पना की गई है, उसे हम कितना साकार कर पाए हैं। नागरिक से समाज और समाज से देश बनता है। सवाल है कि एक देश और व्यक्ति के रूप में आज हम कहां खड़े हैं, इसका एक सिंहावलोकन करना जरूरी है। भारत जीवंत लोकतंत्र का एक जीता-जागता उदाहरण है। यहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों की आस्था है। विरोधी विचारों का सम्मान लोकतंत्र को ताकत देता आया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी पहचान बनाई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर गंभीर मतभेद रहे, लेकिन इन मतभेदों ने लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि उसे मजबूती दी है। लोग अपनी पसंद से सरकारें चुनते आए हैं। आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए बीते दशकों में सरकारें जनकल्याणकारी नीतियां और योजनाएं लेकर आईं। योजनाओं का लाभ गरीबों एवं कमजोर वर्गों तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने आम आदमी को सशक्त बनाया है। इन महात्वाकांक्षी योजनाओं से विकास की गति तेज हुई। लेकिन इन विकास योजनाओं के बावजूद देश में गरीबी, पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है। विकास से जुड़ी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। उदारीकरण के दौर के बाद भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। आर्थिक, सैन्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में इसने सफलता की बड़ी छलांग लगाई है।

चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है।

चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने नए-नए कीर्तमान गढ़े हैं। आईटी सेक्टर में देश अग्रणी बना हुआ है। इन उपलब्धियों ने देश को सुपरपावर बनने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर है कि आज भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन सफलताओं एवं उपलब्धियों के बावजूद सामाजिक और नैतिक मूल्यों में ह्रास हुआ है। व्यक्ति से लेकर समाज, राजनीति सभी क्षेत्रों में मूल्यों का पतन देखने को मिला है। सत्ता, पावर, पैसा की चाह ने लोगों को भ्रष्ट और नैतिक रूप से कमजोर बनाया है। बेहतर समाज और राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। तभी जाकर एक बेहतर भारत और 'न्यू इंडिया' के सपने को साकार किया जा सकेगा।

आधी आबादी को अब भी पर्याप्त अवसरों की दरकार

सशक्तिकरण

सुशील देव

वरिष्ठ पत्रकार

इस बात में कोई दो मत नहीं कि संविधान ने महिलाओं को ताकत दी, उन्हें सशक्त बनाया है। भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधान में से एक है। भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे प्रगतिशील और समावेशी संविधानों में गिना जाता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब देश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं से जूझ रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट समझ रखी कि लोकतंत्र तब तक अधूरा है, जब तक समाज की आधी आबादी-महिलाएं-समान अधिकारों और अवसरों से वंचित रहेंगी। सदियों से चली आ रही लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से, संविधान ने महिलाओं को समानता, गरिमा और सशक्तिकरण का आधार प्रदान किया है।

संविधान के मौलिक अधिकार : समानता का आधार

संविधान के भाग में वर्णित मौलिक अधिकार महिलाओं के सशक्तिकरण की नींव हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में इन्होंने विशेष महत्त्व रखा है।

कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14): यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। महिलाओं के लिए यह मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि यह लैंगिक आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। उदाहरणस्वरूप, संपत्ति अधिकार या शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलते हैं।

भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15): राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण या विशेष योजनाएं। इससे महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में विशेष सहायता मिली है।

मातृत्व राहत (अनुच्छेद 42): राज्य को महिलाओं के लिए मानवीय कार्य स्थितियां और मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इससे मातृत्व अवकाश, प्रसव सहायता और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे कानून बने हैं, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961।

शिक्षा और स्वास्थ्य (अनुच्छेद 45 और 47): ये प्रावधान महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, जिससे योजनाएं जैसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संभव हुए हैं। ये सिद्धांत महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं।

महिला आरक्षण विधेयक (2023) के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

पंचायती राज और राजनीतिक सशक्तिकरण: आरक्षण की शक्ति

संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1992) के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पंचायतों और नगर निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण ने ग्रामीण भारत में लाखों महिलाओं को पहली बार सत्ता और निर्णय प्रक्रिया से जोड़ा। यह एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा दी। हाल ही में, महिला आरक्षण विधेयक (2023) के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद जमीनी सच्चाई कई सवाल खड़े करती है। आज भी देश में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर चिंताजनक रूप से कम है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के बावजूद उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सीमित है। कार्यस्थलों पर असमान वेतन, असुरक्षा और भेदभाव की शिकायतें आम हैं। वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव होगा जब कानून, प्रशासन और समाज-तीनों एक साथ आगे बढ़ें। संविधान ने रास्ता दिखाया है, अब जिम्मेदारी हमारी है कि उस रास्ते पर ईमानदारी से चला जाए, ताकि महिलाएं सिर्फ अधिकारों की धारक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की बराबर की सहभागी बन सकें।

बाबा साहेब आंबेडकर की दूरदर्शी सोच का प्रतिबिंब

मिसाल

योगेश कुमार सोनी

वरिष्ठ पत्रकार

दृढ़ निश्चय कैसे जीत का संकल्प होता है, यह मिसाल हमारे देश के संविधान के रूप व प्रारूप में देखने मिलती है। देश ही नहीं, विश्व में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान की गंभीरता को सम्मान दिया जाता है। इसका कारण है कि बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान आधुनिक भारत की आधारशिला है, जो समानता, स्वतंत्रता और एकता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह संविधान न केवल देश की एकता-अखंडता को बनाए रखता है, बल्कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, न्याय और अवसर की समानता की गारंटी देकर एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण करता है। हमारे संविधान में जितनी रचनात्मक चीजें हैं, उतनी कहीं नहीं देखी जाती। इसमें आश्चर्य व खुशी की बात यह है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और उसे अपनाया गया, जिसके बाद यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। आज 75 वर्षों बाद भी इसका महत्व उतना ही देखने को मिला, जितना उस समय था।

संविधान, उस कालखंड में जनसंख्या व उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन बाबा साहब की सोच इतनी तीव्र थी कि उन्होंने खाका इस तरह से तैयार किया कि वह आज तक सकारात्मक रूप से अमल में लिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत जैसे देश के लिए इतना बड़ा कानूनी स्ट्रक्चर तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं था, चूंकि यहां प्रारंभिकता से सभी धर्मों का समावेश रहा है और मौलिक अधिकारों को लेकर हमेशा एक लडाई सी रही है। जानकारी दे दी जाए कि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे जिसकी विश्व पटल पर आज भी प्रशंसा होती हैं। चूंकि आकस्मिक व विषम परिस्थितियों के बावजूद देश के संविधान को धैर्य, विश्वास व ठहरावट के साथ निर्मित किया गया था। बाबा साहब ने जिस समाज का सपना देखा था, वो समता, बंधुता और न्याय पर आधारित था। यूं तो

बाबा साहेब की सोच इतनी तीव्र थी कि उन्होंने खाका इस तरह से तैयार किया कि आज 75 वर्षों बाद भी इसका महत्व उतना ही देखने को मिला, जितना उस समय था।

बाबा साहब के बचपन से लेकर भारत और विलायत में उच्च शिक्षा हासिल करने तक उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना अपमान सहा इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को हैं लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि वो जितने कामयाब राजनीतिज्ञ थे, उतने ही कामयाब वकील भी थे। उन्होंने कई देशों के संविधान की पढ़ाई करने में काफी समय व्यतीत किया। उस दौर के सबसे शिक्षित व समझदार वकील होने की वजह से उन्होंने संविधान में उन तकनीक कानून का प्रयोग किया, जिसमें किसी भी धर्म व जाति के लोगों में किसी भी कोई भी नकारात्मक नहीं देखी गई। वैसे तो किसी भी देश का संविधान देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है जो समाज को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और नियमों को निर्धारित करता है। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, न्याय और समानता को बढ़ावा देता है और नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देता है। बीते कुछ वर्षों में कुछ राज्य सरकारों व नेताओं ने संविधान पर बहुत राजनीति की और देश में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की। आज राजनीति में संविधान को एक मुद्दे के रुप में भुनाने का काम किया जा रहा है। भारत में राजनीतिक दल अक्सर संविधान का हवाला देकर अपनी विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा देने लगे हैं, जिसे विभिन्न आलोचक राजनीतिक दांव-पेंच के रूप में देखते हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही अक्सर संविधान की रक्षा या उसके उल्लंघन का आरोप लगाकर एक-दूसरे पर निशाना साधते हैं क्योंकि संविधान में राजनीतिक दलों का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन उनको यह समझना होगा कि उनके इस व्यवहार से हम आने वाली पीढ़ी के लिए गलत काम कर रहे हैं। जब हम ही संविधान की गरिमा को नहीं समझेंगे तो देश के युवाओं पर इसका क्या असर पडेगा, यह उनको समझना पड़ेगा। अब इसके नकारात्मक पहलू देखने को मिलने भी लगे। हमारे संविधान में भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है इसलिए हर किसी युवा को अपनी सोच व उपज के आधार पर अपनी सरकार चुनने का हक है। हमें यह शपथ लेनी होगी कि कोई भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की आलोचना व दुरुपयोग न करें। हम स्वतंत्र भारत के वासी हैं और यह संचालन प्रक्रिया को लेकर हम उस दिशा में लेकर जाएंगे जो सब के हित के लिए कार्य करे।

भारतीय संविधान की प्रासंगिकता आज भी बरकरार

विशेषता

योगेंद्र माथुर

स्वतंत्र पत्रकार

भारत का संविधान देश के लोकतंत्र का मूल आधार है। यह भारत की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया और इसी दिन भारत को 'गणतंत्र' घोषित कर डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

वैश्विक परिदृश्य में आज जब दुनिया के अधिकांश छोटे-बड़े देशों में सत्ता व शासन प्रणाली को लेकर जन असंतोष व उथल-पुथल देखने को मिल रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारतीय गणतंत्र अपनी उत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्था की मजबूत बुनियाद पर शान से परचम लहराता हुआ दिख रहा है। अपनी तमाम खूबियों के साथ इसकी प्रासंगिकता आज भी यथावत बनी हुई है।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया: 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति सुनिश्चित होने के पश्चात भारत के कर्णधारों को एक ऐसे मार्गदर्शक विधान की आवश्यकता महसूस हुई जिसके प्रकाश में लोकतांत्रिक पद्धति से देश का सुचारू व निर्बाध रूप से संचालन होता रहे। अतः इसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें तमाम वर्गों व विचारधाराओं के बुद्धिजीवी सदस्यों को शामिल किया गया। केबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार नवंबर 1946 में गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई।

इसकी अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों यथा प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति व झंडा समिति आदि बनाई गई। इनमें प्रमुख प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया और डॉ. बी.आर. अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। भारत के इस संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि लोकतंत्र के तीनों अंगों यथा विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में टकराव न हो इसके लिए इनके अधिकारों, कर्तव्यों व सीमाओं का निर्धारण इस संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है

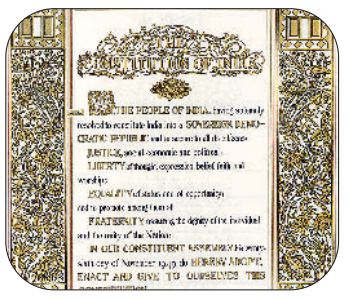

आचार-व्यवहार व अनुशासित जीवन जीना हमारी प्रतिबद्धता होना चाहिए। संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति समर्पण भाव रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

कि कोई लोकतंत्र का कोई भी अंग अपने अधिकारों, सीमाओं व मर्यादा का उल्लंघन न करें।

शक्तियों का बंटवारा : संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र व राज्य की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। ऐसे विषय जो तीनों सूची में न हों अर्थात अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद को दी गई है। इसमें नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो नागरिक कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है ताकि नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना स्थापित हो। हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 1976 के 42 वें संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए हैं। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्यिका के अनुरूप एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। हालांकि इन्हें लागू करवाने के लिए कोई कानूनी या संवैधानिक दबाव नहीं है। भारत का संविधान काफी हद तक लचीला है। इसमें समय, परिस्थितियों व आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान में पहला संशोधन सन् 1951 में हुआ था। इस संशोधन में राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। तब से अब तक संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन संविधान का मूल स्वरूप यथावत बना हुआ है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है, जिसमें दृढ़ता व लचीलेपन के बीच एक आदर्श संतुलन है। दुनिया के तेजी से बदलते आंतरिक व वैश्विक परिदृश्य में विघटनकारी, विभाजनकारी एवं विनाशकारी शक्तियों द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों का सामना करने में कुछ ही देश सफल हो सके हैं। दूसरी ओर, भारत का संविधान देश के नागरिकों द्वारा अंगीकृत किए जाने के बाद से अब तक सतत गतिशीलता व प्रासंगिकता के साथ समृद्ध व सशक्त होता रहा है।

कहा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। अतः संविधान के अनुसार आचार-व्यवहार व अनुशासित जीवन जीना हमारी प्रतिबद्धता होना चाहिए। संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों व सिद्धांतों के प्रति समर्पण भाव रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

सीरीज जीत की दहलीज पर भारत, किशन के प्रदर्शन से संजू पर बढ़ा दबाव

गुवाहाटी में आज शाम 7 बजे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20

एजेंसी ▶▶| गुवाहाटी

पहले दोनों मैच आसानी से जीतने के बाद भारत रविवार 25 जनवरी को होने वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत हासिल करके पांच मैच की श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा, जिसमें संजू सैमसन के प्रदर्शन पर सभी की निगाह टिकी रहेंगी क्योंकि ईशान किशन ने पिछले मैच में शानदार वापसी करके उन पर दबाव बढ़ा दिया है।

किशन की शानदार पारी से इस बात पर बहस फिर से शुरू हो जाएगी कि अभिषेक शर्मा का पसंदीदा सलामी जोड़ीदार कौन होना चाहिए, क्योंकि सैमसन अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। टी20 विश्व कप के शुरू होने में अब केवल दो सप्ताह का समय बचा है और इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे तीन मैच खेलने हैं। ऐसे में भारत की टीम संयोजन काफी हद तक तय लग रहा है।

सैमसन मौके का फायदा उठाने में नाकाम

भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केवल कुछ स्थान को लेकर ही टीम चिंतित होगी, जिनमें से एक स्थान फिलहाल सैमसन के पास है। किशन की 32 गेंदों पर खेली गई शानदार 76 रनों की पारी ने संजू पर दबाव बढ़ा दिया है। टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की जगह अभिषेक के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में बहाल किए गए सैमसन मौकों का पूरा फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं, जबकि उन्हें काफी मैच खेलने का मौका मिला है। गिल तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए थे और इसलिए संजू को अंतिम एकादश में शामिल करने के साहसिक फैसले के तहत उन्हें बाहर कर दिया गया।

सूर्यकुमार फॉर्म में लौटे

भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी चिर परिचित फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने 37 गेंद पर 82 रन बनाकर पिछले 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों के बाद अपना पहला अर्धशतक जड़ा।

भारत पांच मैच की श्रृंखला में 2-0 से आगे है लेकिन उसे किसी तरह के मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वापसी करने में माहिर है जैसा उसने इससे पहले खेली गई वनडे श्रृंखला में किया था। पिछले मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक पहली गेंद पर आउट हो गए थे और वह यहां बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे।

रणनीतिक बदलावों पर विचार कर सकती है न्यूजीलैंड

मिचेल सैंटनर की अगुवाई वाली टीम कुछ रणनीतिक बदलावों पर विचार कर सकती है। वह शानदार फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेज सकता है। न्यूजीलैंड की आमतौर पर मजबूत मानी जाने वाली फील्डिंग इस बार बेहद निराशाजनक रही। सैंटनर और ईश सोढ़ी सहित उसके खिलाड़ियों ने कई कैच छोड़े। न्यूजीलैंड को इस विभाग में तुरंत सुधार करने की जरूरत है।

टीमें इस प्रकार

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा।

न्यूजीलैंड : मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉक्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।

खबर संक्षेप

दुबई डेजर्ट क्लासिक: शुभंकर और युवराज कट से चूके

दुबई। भारत के शुभंकर शर्मा और युवराज सिंह संधू ने दूसरे दौर में भी खराब प्रदर्शन किया, जिससे वह हीरो दुबई डेजर्ट क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट के कट में जगह नहीं बना पाए। प्रतिष्ठित रोलेक्स सीरीज प्रतियोगिता में पदार्पण कर रहे संधू ने 73 और 73 के राउंड खेले, जबकि शर्मा लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे और शुरुआती 74 के बाद उन्होंने दूसरे दौर में निराशाजनक 77 का स्कोर बनाया। इस बीच पूर्व मास्टर्स चैंपियन पैट्रिक रीड ने दूसरे दौर में 66 का स्कोर बनाकर एक शॉट की मामूली बढ़त हासिल कर ली।

सूर्या ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज : शिवम दुबे

रायपुर। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इस स्टार बल्लेबाज ने धमाकेदार पारी खेलकर दिखा दिया कि वह खेल के सबसे छोटे प्रारुप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। सूर्यकुमार ने 23 पारियों के बाद पहली बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया, जिससे अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया।

ओलंपिक के लिए भारत के दो खिलाड़ियों के चयन पर रोक लगी

नई दिल्ली। इटली के मिलान और कोर्टिना में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अब दो सप्ताह से भी कम समय बचा है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति द्वारा दो भारतीय खिलाड़ियों के चयन पर फिलहाल रोक लग गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अंतिम निर्णय को लंबित कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में क्रॉस-कंट्री स्कीयर मंजीत ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्रॉस-कंट्री स्कीइंग स्पर्धा में स्टांजिन लुंडुप का नाम भेजे जाने के आईओए के फैसले को चुनौती दी है। मंजीत ने दलील दी है कि अंतरराष्ट्रीय स्की और स्नोबोर्ड महासंघ (एफआईएस) की रैंकिंग में उनसे ऊपर होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने याचिका में चयन प्रक्रिया में प्रक्रियागत खामियों और हितों के टकराव के आरोप भी लगाए हैं।

स्केटर सचिन ने हरियाणा को शीर्ष पर बरकरार रखा

लेह (लद्दाख)। स्कार्मा त्सुल्टिम, शबाना ज़ारा, तस्निया शमीम और इंशा फातिमा की महिला रिले टीम ने 2000 मीटर शॉर्ट ट्रैक रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को यहां नवांग दोरजे स्तोबदान (एनडीएस) स्टेडियम में खेले जा रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स (केआईडब्ल्यूजी) 2026 में मेजबान लद्दाख को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। हरियाणा ने शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग में दो और स्वर्ण पदक अपने नाम कर कुल चार स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन : गर्मी के कारण रोके गए आउटडोर गेम

भीषण गर्मी से जूझे टेनिस सितारे, सिनर, कीज पेगुला और अनिसिमोवा जीते, ओसाका बाहर

एजेंसी ▶▶| मेलबर्न

यानिक सिनर ने भीषण गर्मी से जूझने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में प्रवेश करके खिताबी हैट्रिक बनाने की अपनी कवायद जारी रखी। सिनर जब हाथ पैरों में ऐंठन को दूर करने के लिए जूझ रहे थे और तीसरे सेट में 1-3 से पिछड़ रहे थे तब भीषण गर्मी के नियमों ने उन्हें बचा लिया। शनिवार दोपहर को रॉड लेवर एरिना में खेल कुछ मिनटों के लिए रोक दिया गया और छत बंद कर दी गई। इसके बाद सिनर ने नई ऊर्जा के साथ कोर्ट पर कदम रखा। उन्होंने अगले छह गेम में से पांच जीतकर 85वीं रैंकिंग के खिलाड़ी इलियट स्पिजिरी को 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 से पराजित किया।

सिनर अगले दौर में इटली के हमवतन खिलाड़ी लुसियानो डार्डेरी का सामना करेंगे। इटली के तीन खिलाड़ी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इनमें तीसरे खिलाड़ी पांचवीं वरीयता प्राप्त लोरेंजो मुसेटी हैं, जिन्होंने जॉन केन एरिना में खेले गए मैच में टॉमस माचक को 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 से हराया। इस मैच को भी पांचवें सेट में छत बंद करने के लिए थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था। विश्व में आठवें नंबर के खिलाड़ी बेन शेल्टन भी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने मार्गरेट कोर्ट एरिना पर मोनाको के वैलेंटीन वाचेरोट को 6-4, 6-4, 7-6 (5) से पराजित किया। वहीं ओसाका ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है।

अमांडा ने बनाई अंतिम 16 में जगह

अमेरिका की एक अन्य खिलाड़ी और चौथी वरीयता प्राप्त अमांडा अनिसिमोवा ने हमवतन पेटन स्टर्न्स को 6-1, 6-4 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। सातवें दिन खेल निर्धारित समय से एक घंटा पहले शुरू हुआ, क्योंकि पूर्वानुमान में 40 डिग्री सेल्सियस (104 फ़ारेनहाइट) तक के तापमान की आशंका थी। शुरुआती मैचों के दौरान तापमान उस स्तर तक नहीं पहुंचा। इस दौरान तापमान 32 डिग्री सेल्सियस (89 फ़ारेनहाइट) रहा।

कीज और जेसिका की चौथे दौर में एंट्री

महिला वर्ग में मौजूदा चैंपियन मैडिसन कीज और उनकी हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने भी सीधे सेटों में जीत दर्ज करके चौथे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका आमना सामना होगा। नौवीं वरीयता प्राप्त कीज ने रोड लेवर एरिना में खेले गए पहले मैच में कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-3 से हराया, जबकि छठी वरीयता प्राप्त पेगुला ने मार्गरेट कोर्ट एरिना में खेले गए पहले मैच में ओक्साना सेलेखमेतेवा को 6-3, 6-2 से पराजित किया।

चोट के कारण हटीं ओसाका

जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर से मैच से पहले हटने का फैसला किया। चार बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन ओसाका को तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलियाई क्वालिफायर मैडिसन इंग्लिस के खिलाफ खेलना था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि अपने पिछले मैच के बाद उन्हें 'अपने शरीर की एक ऐसी समस्या पर ध्यान देना है, जिसे इलाज की जरूरत है।' ओसाका ने पोस्ट किया, 'मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित थी और यह सफर मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था इसलिए यहां रुकना मेरे दिल तोड़ने वाला है। लेकिन मैं और नुकसान का जोखिम नहीं उठा सकती ताकि मैं कोर्ट पर वापस आ सकूं।' टूर्नामेंट द्वारा बाद में जारी किए गए बयान में ओसाका ने कहा कि उन्हें पेट के बाईं ओर दिक्कत थी।

भांबरी तीसरे दौर में, बालाजी बाहर

भारत के युकी भांबरी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल के तीसरे दौर में जगह बनाई लेकिन एक अन्य भारतीय खिलाड़ी एन श्रीराम बालाजी दूसरे दौर से बाहर हो गए। भांबरी और उनके स्वीडिश साथी आंद्रे गोरानसन की 10वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने दूसरे दौर के मुकाबले में सैंटियागो गोंजालेज और डेविड पेल की गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी को 4-6, 7-6(5), 6-3 से हराया। इससे पहले बालाजी और ऑस्ट्रिया के उनके जोड़ीदार नील ओबरलीट्नर को अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के माटे पाविच की चौथे वरीयता प्राप्त जोड़ी से 5-7, 1-6 से हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मेलबर्न पार्क के शो कोर्ट पर अपनी निरंतरता और बड़े मैचों के खेलने का अच्छा नमूना पेश किया।

अंडर-19 विश्व कप

भारत ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया

- भारत की लगातार तीसरी जीत
- आयुष म्हात्रे की फिफ्टी, अंबरीश को चार विकेट

एजेंसी ▶▶| बुलावायो

कप्तान आयुष म्हात्रे की 27 गेंदों में खेली गई 53 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने शनिवार को यहां अंडर-19 विश्व कप में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से सात विकेट से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए बारिश से प्रभावित 37-37 ओवर के इस मुकाबले को बेहद आसानी से अपने नाम कर टूर्नामेंट में दबदबा कायम रखा। न्यूजीलैंड ने 22 रन तक पांच विकेट गंवा दिये थे जिसके बाद बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। मैच दोबारा शुरू होने पर इसे 37-37 ओवर का कर दिया गया। न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में रही और 69 रन पर सात विकेट गंवा बैठी। भारतीय गेंदबाजों के निरंतर प्रहार के चलते टीम 36.2 ओवर में 135 रन पर ढेर हो गई। भारत ने संशोधित लक्ष्य 130 रन का पीछा करते हुए महज 13.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले तेज गेंदबाजों के लिए माकूल परिस्थितियों में टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया। आर.एस. अम्ब्रिश (29 रन पर चार विकेट) और हेनिल पटेल (23 रन पर तीन विकेट) ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके दिये जिससे टीम उबरने में नाकाम रही। न्यूजीलैंड की ओर से शीर्ष पांच बल्लेबाजों में केवल स्नेहित रेड्डी (10) ही दो अंकों तक पहुंच सके। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ देर तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। जैकब कॉटर (23), कैलम सैमसन (37) और सेल्विन संजय (28) ने अंत में कुछ उपयोगी रन जोड़े, लेकिन वे भारतीय गेंदबाजों के सामने अपनी पकड़ नहीं बना सके।

भारतीय टीम का ऐलान

ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट के लिए प्रतिका वैष्णवी और क्रांति टीम में शामिल

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

पिछले साल महिला वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के अलावा बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा और तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को 6 से 9 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारत की 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी।

यह टेस्ट मैच 15 फरवरी से शुरू होने वाले सीमित ओवरों के मैचों (तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे) के बाद खेला जाएगा। युवा विकेटकीपर कमलिनी चोट के कारण भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गई हैं और चयनकर्ताओं ने उनकी जगह उमा छेत्री को टी20 और वनडे टीमों में शामिल किया है।

टेस्ट टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे।

राइजिंग स्टार के लिए टीम

हुमैरा काजी, वृंदा दिनेश, अनुष्का शर्मा, दीया यादव (फिटनेस पर निर्भर), तेजल हसब्निस, नंदनी कश्यप (विकेटकीपर), ममता एम (विकेटकीपर, फिटनेस पर निर्भर), राधा यादव (कप्तान), सोनिया मेंढिया, मिन्नू मणि, तनुजा कंवर, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, जिन्तामणि कलिता, नंदनी शर्मा।

राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए टीम का ऐलान

चयनकर्ताओं ने एसीसी राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन भी कर लिया है, जिसकी कप्तानी बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव करेंगी। प्रतिभाशाली बल्लेबाज अनुष्का शर्मा को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण टीम में शामिल किया गया है। यह टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी के बीच थाईलैंड में खेला जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट में यूएई (13 फरवरी), पाकिस्तान ए (15 फरवरी) और नेपाल (17 फरवरी) के खिलाफ खेलेगा।

स्प्राट चैंपियंस स्क्वाश के दूसरे दौर में अनाहत

नई दिल्ली। भारत की शीर्ष महिला स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अंतिम क्षणों में कुछ विषम परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद लूसी टरमेल को हराकर न्यूयॉर्क में चल रहे स्प्राट टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। विश्व में 31वें नंबर की खिलाड़ी अनाहत ने पीएसए प्लैटिनम प्रतियोगिता में इंग्लैंड की टरमेल को 11-3, 11-6, 9-11, 13-11 से हराया। अब उनका मुकाबला जापान की छठी वरीयता प्राप्त सतोमी वातानाबे से होगा। इस बीच पुरुषों की विश्व रैंकिंग में 29वें स्थान पर काबिज भारत के अभय सिंह स्पेन के इकर पजारेस के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद 4-11, 11-4, 7-11, 11-3, 3-11 से हार गए।

डब्ल्यूपीएल: कैपिटल्स सात विकेट से जीती, आरसीबी को मिली पहली हार

भाषा ▶▶| वडोदरा

दिल्ली कैपिटल्स ने अनुशासित गेंदबाजी के बाद लौरा वोलवार्ट 42 रन की नाबाद पारी से शनिवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में तालिका में शीर्ष पर चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 26 गेंद रहते सात विकेट से हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की। आरसीबी को टूर्नामेंट में पहली हार का मुंह देखना पड़ा जिसके छह मैच में पांच जीत से 10 अंक हैं। इस हार के बावजूद वह शीर्ष पर कायम हैं। दिल्ली कैपिटल्स छह मैच में तीसरी जीत से छह अंक से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों ने आरसीबी को 20 ओवर में महज 109 रन पर समेट दिया। आरसीबी की केवल तीन खिलाड़ी ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सकी जिसमें कप्तान स्मृति मंधाना 38 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट जबकि मरिजान काप, चिनेल हेनरी और मीनू मणि ने दो दो विकेट झटके।

श्री चरणी ने एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य बड़ा नहीं था और दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवर में तीन विकेट पर 111 रन बनाकर इसे हासिल कर लिया। उसके लिए लौरा वोलवार्ट 38 गेंद में 42 रन बनाकर नाबाद रहीं। आरसीबी के लिए सयाली सतघरे ने पावरप्ले में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (आठ गेंद में 16 रन) और लिजेल ली (06) के विकेट लेकर शुरूआती झटके दिए।

▶▶| बेंगलुरु छह मैच में पांच जीत से 10 अंक के साथ शीर्ष पर

▶▶| कैपिटल्स छह मैच में तीसरी जीत से छह अंक से दूसरे स्थान पर

एसए20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप का चमत्कार

लगातार चौथी बार फाइनल में काव्या मारन की सनराइजर्स

एजेंसी ▶▶| जोहानिसबर्ग

सेनुरान मुथुसामी की फिरकी के जादू के बाद जेम्स कोल्स की तूफानी पारी से सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने क्वालीफायर दो में पार्ल रॉयल्स पर सात विकेट की एकतरफा जीत के साथ लगातार चौथी बार एसए20 क्रिकेट लीग के फाइनल में जगह बनाई।

रॉयल्स की टीम मुथुसामी (15 रन पर तीन विकेट) और एनरिच नोर्किया (31 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने काइल वेरेने (नाबाद 52, 46 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) के नाबाद अर्धशतक के बावजूद सात विकेट पर 114 रन ही बना सकी। इसके जवाब में दो बार के चैंपियन और गत उप विजेता सनराइजर्स ने कोल्स की 19 गेंद में तीन छक्कों और चार चौकों से नाबाद 45 रन की पारी की बदौलत 11.4 ओवर में तीन विकेट पर 117 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। वांडरर्स स्टेडियम की धीमी और स्पिन की अनुकूल पिच पर मुथुसामी और कोल्स (15 रन पर एक विकेट) की बाएं हाथ की स्पिन जोड़ी ने मिलकर आठ ओवर में 30 रन पर चार विकेट लेकर रॉयल्स की टीम को हमेशा दबाव में रखा।

सनराइजर्स को डिकॉक ने दिलाई तेज शुरुआत

रविवार को केपटाउन में होने वाले फाइनल में अब सनराइजर्स की भिड़ंत प्रिटोरिया कैपिटल्स से होगी और टीम क्वालीफायर एक में इस टीम के खिलाफ मिली सात विकेट की हार का बदला चुकता करके तीसरी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगी। लक्ष्य का पीछा करने उतरे सनराइजर्स को क्विंटन डिकॉक ने तेज शुरुआत दिलाई। डिकॉक (25 रन, 12 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) ने बाएं हाथ के स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन पर दो चौकों के साथ शुरुआत की और फिर हार्डस विलजोएन की लगातार गेंदों पर दो छक्के और एक चौका मारा। डिकॉक हालांकि फोर्टुइन के अगले ओवर में सीधी गेंद को चूककर बोल्ड हो गए।

रॉयल्स के पावर प्ले में गिरे 3 विकेट

रॉयल्स की टीम पावर प्ले में तीन विकेट पर 31 रन ही बना सकी। मुथुसामी ने सातवें ओवर में एसा ट्राइब (01) को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच कराके रॉयल्स को चौथा झटका दिया। पावर प्ले के बाद अगले छह ओवर में रॉयल्स की टीम सिर्फ 17 रन ही बना सकी, जो सनराइजर्स के गेंदबाजों के दबदबे को दर्शाता है। वेरेने ने कोल्स पर पारी के पहले छक्के के साथ 13वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया जबकि अगले ओवर में सिकंदर रजा ने क्रिस ग्रीन पर छक्का जड़ा। रजा (19) 15वें ओवर में मुथुसामी पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए और डिकॉक ने उन्हें स्टंप करने में कोई गलती नहीं की।

खबर संक्षेप

यूएस में बर्फीला तूफान 10 हजार उड़ानें रद्द

डलास। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से सप्ताहांत के दौरान करीब 10,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में भारी तबाही होने की आशंका है और कई दिनों तक बिजली गुल रहने और प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक लगभग 14 करोड़ लोगों के शीतकालीन तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। उत्तरी कैरोलिना तक के क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। विशेष रूप से बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाला नुकसान तूफान के बराबर हो सकता है।

मेटा ने किशोरों के लिए 'एआई कैरेक्टर' बैन किया

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने कहा है कि वह किशोरों के लिए 'एआई कैरेक्टर' तक पहुंच को अस्थायी रूप से रोक रही है। कंपनी ने शुक्रवार को एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मालिकाना हक वाली कंपनी 'मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक' ने बताया कि आने वाले कुछ हफ्तों में किशोरों को 'एआई कैरेक्टर' (एआई आधारित डिजिटल किरदार) तक पहुंच नहीं दी जाएगी और यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक इसका नया और बेहतर संस्करण तैयार नहीं हो जाता। कंपनी ने कहा कि यह फैसला उन सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होगा जिन्होंने मेटा में ऐसी जन्मतिथि दर्ज की है जिससे वे नाबालिग साबित होते हैं।

मानवाधिकार परिषद में ईरान के साथ खड़े हुए भारत, पाकिस्तान और चीन

ईरान के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव के विरोध में की वोटिंग, बताया पश्चिमी एजेंडा

एजेंसी ▶▶ जिनेवा

भारत ने सीधे विरोध में वोट डालकर यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि वह दोहरे मापदंडों के खिलाफ खड़ा है और मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेगा। 25 वोट होने के कारण यह प्रस्ताव परिषद में पारित हो गया

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 39वें विशेष सत्र में शुक्रवार को भारत ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को चौंका दिया। दरअसल, इस सत्र में ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर पश्चिमी देशों की ओर से एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन भारत ने खुले तौर पर इसमें ईरान का साथ दिया और इस प्रस्ताव के विरोध में वोट कि या । पश्चिमी देशों की ओर से प्रस्ताव संख्या ए/एचआरसी/ एस/एल1 पेश किया गया, जिस पर मतदान किया गया।

- 25 देशों ने पक्ष में दिए वोट, प्रस्ताव पारित

इस प्रस्ताव का मकसद 'इस्लामी गणराज्य ईरान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति' की निंदा करना था। खासतौर पर ईरान में पिछले महीने भड़के विरोध प्रदर्शनों और हजारों लोगों की मौतों के मद्देनजर यह प्रस्ताव लाया गया था। पश्चिमी देश चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र ईरान पर सख्त रुख अपनाए। लेकिन वैश्विक दक्षिण के कई अहम देशों ने इसे खारिज किया और पश्चिमी एजेंडा करार दिया।

भारत की विदेश नीति में बदलाव का संकेत

यूनाइटेड नेशन्स

14 देश तटस्थ रहे

वहीं, वैश्विक दक्षिण के कई देशों ने मतदान से दूरी बनाई। कुल 14 सदस्यों देशों ने मतदान से परहेज किया। यानी इन देशों ने वोटिंग के दौरान तटस्थ रहने का विकल्प चुना। इनमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कतर, कुवैत, मलयेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं।

47 सदस्यीय परिषद में पेश किया गया

प्रस्ताव में तेहरान से मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने की मांग की गई थी। इसे 47 सदस्यीय परिषद में पेश किया गया। परिषद के 25 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। इनमें प्रमुख रूप फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, चिली जैसे देश शामिल थे। जबकि 14 सदस्य देश इसमें तटस्थ रहे। 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। जिनमें भारत और चीन भी शामिल थे।

...अब भारत पश्चिम के दबाव में नहीं

पारंपरिक रूप से विवादित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर तटस्थ रहने की नीति अपनाता रहा है। लेकिन इस बार उसने सीधे विपक्ष में वोट दिया है। इसके भारत की विदेश नीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अमेरिका की ओर से भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव है। यूएनएचआरसी में अपने वोट से भारत ने स्पष्ट किया है कि वह पश्चिम के किसी भी दबाव में नहीं आएगा। ईरान के साथ भी भारत के मजबूत संबंध रहे हैं।

तटस्थ रहने के बजाए इस बार भारत की सीधे 'ना'

आम तौर पर भारत इस तरह के विवादित प्रस्तावों पर सीधे 'हां' या 'ना' वोट देने की बजाए 'तटस्थ' रहने की कूटनीति अपनाता रहा है। लेकिन इस बार उसने तटस्थ रहने के बजाए सीधे 'ना' वोट किया। जिन देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया उनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, इराक, वियतनाम, इंडोनेशिया और क्यूबा शामिल थे। यह दुर्लभ मौका था, जब किसी अंतरराष्ट्रीय पर भारत और उसके पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान ने एक ही पक्ष की तरफ वोट किया।

दोहरे मापदंडों के खिलाफ भारत

अमेरिकी की ओर से सख्त प्रतिबंध लगाए जाने से ईरान भारत की उर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता रहा। इसके अलावा, रणनीति रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के लिए ईरान भारत के अहम है। भारत ने सीधे विरोध में वोट डालकर यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि वह दोहरा मापदंडों के खिलाफ खड़ा है और मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, 25 वोट होने के कारण यह प्रस्ताव परिषद में पारित हो गया।

जापान ने वीजा नियम बदले

वैध जापान वीजा वाले भारतीय कर सकेंगे 7 अन्य देशों की यात्रा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

हाल ही में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस बैठक के बाद आई जानकारी के अनुसार, जापान ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत जापान का वैध वीजा रखने वाले भारतीय यात्रियों को कई अन्य देशों की यात्रा में भी सुविधा मिलेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

नए नियमों के अनुसार, वैध जापान वीजा वाले भारतीय पासपोर्ट होल्डर अब सात अन्य देशों की यात्रा कर सकेंगे। ये देश यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में स्थित हैं और यात्रा संबंधित देशों की शर्तों पर निर्भर करेगी। इन देशों में जॉर्जिया, फिलीपींस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान, मोंटेनेग्रो और मेक्सिको शामिल हैं।

रणनीतिक साझेदारी के 75 साल पूरे

भारत और जापान वर्ष 2027 में अपनी रणनीतिक साझेदारी के 75 वर्ष पूरे करेंगे। वहीं, इसी साल जापान की 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (एफओआईपी) रणनीति की 10वीं वर्षगांठ भी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग खास महत्व रखता है। हाल ही में हुई बैठक में दोनों देशों ने 2026 की पहली तिमाही में प्राइवेट-सेक्टर डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी शुरू करने पर सहमति जताई है। इस संवाद में सेमीकंडक्टर, जरूरी मिनरल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), क्लीन एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स-इन पांच प्राथमिक क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा।

भारतीय मूल के व्यक्ति ने पत्नी को गोली मारी, 3 रिश्तेदारों की भी हत्या

जॉर्जिया (एजेंसी)। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में पारिवारिक विवाद के कारण भारतीय मूल के 51 वर्षीय व्यक्ति को पत्नी और तीन रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। ग्विनेट काउंटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि आरोपी विजय कुमार को लॉरेंसविले शहर में उस आवास से थोड़ी ही दूरी पर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मरने वालों की पहचान कुमार की पत्नी मीमू डोगरा (43) जो भारतीय नागरिक है और रिश्तेदारों गौरव कुमार (33), निधि चंदर (37) और हरीश चंदर (38) के रूप में की है। अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने गोलीबारी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अटलांटा स्थित अपने घर में कुमार और डोगरा के बीच कहासुनी शुरू हो गई और वे अपने 12 वर्षीय बच्चे के साथ बुक आइवी कोर्ट स्थित अपने रिश्तेदारों के घर चले गए।

आरोपी विजय कुमार पत्नी मीमू डोगरा के साथ।

फ्री ट्रेड और डिफेंस डील पर लगेगी मुहर

भारत पहुंचीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला, आज आएंगे कोस्टा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के रिश्तों में एक नया और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन अपनी चार दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी रविवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उर्सुला वॉन डेर लेन का स्वागत किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने इसे रणनीतिक साझेदारी का 'अगला चरण' बताया। यह यात्रा दो वजहों से खास है- पहला, ये दोनों यूरोपीय दिग्गज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, और दूसरा, 27 जनवरी को होने वाली बैठक में कई बड़े व्यापारिक समझौतों पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय नेताओं के बीच होने वाली इस शिखर वार्ता में सबसे बड़ा आकर्षण 'मुक्त व्यापार समझौता' है। लंबे समय से अटके इस समझौते के पूरा होने की घोषणा इस बैठक में की जा सकती है। दोनों पक्ष एक रणनीतिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप देंगे। साथ ही भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोप में काम करना और आना-जाना आसान बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

गांव में 300 आवारा कुत्तों को मार डाला, सरपंच पर केस दर्ज

हैदराबाद। तेलंगाना में आवारा कुत्तों को कथित तौर पर जान से मारने की एक और घटना सामने आई है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि जगित्याल जिले में करीब 300 कुत्तों को मार दिया गया। कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि हालिया घटना के बाद राज्य में अब तक इस तरह की घटनाओं में मारे गए कुत्तों की संख्या 900 तक पहुंच गई है। कुत्तों को मारने का यह कृत्य सरपंच समेत कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इशारे पर किया गया है। पंचायत चुनावों से पहले ग्रामीणों से किए गए वादों के तहत आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया।

- तेलंगाना राज्य में अब तक 900 कुत्ते मारे गए

100 कुत्तों को दिया था जहर

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से दर्ज कराई गई एक अन्य शिकायत के अनुसार, 19 जनवरी को हैदराबाद के पास याचारम गांव में 100 कुत्तों को कथित तौर पर जहर देकर मार दिया गया था, हालांकि तत्काल मौके से 50 मरे हुए कुत्ते बरामद हुए थे। इससे पहले इसी महीने हनमकोंडा जिले में श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में करीब 300 आवारा कुत्तों की कथित तौर पर मारे जाने के मामले में पुलिस ने दो महिला सरपंचों और उनके पतियों सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जातिगत भेदभाव को लेकर आक्रोश

यूजीसी रेगुलेशन का देशभर में जमकर विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

यूजीसी ने हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 लागू किया है। इसे लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक संग्राम मचा है। अब इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अर्जी में यूजीसी नियमावली, 2026 के नियम 3(सी) को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह नियम जाति-आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है। इस बात के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव शिकायत का अधिकार नहीं है। इस लिहाज से यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो यूजीसी रेगुलेशन, 2026 के रेगुलेशन 3(सी) को असंवैधानिक घोषित करे। इसके लागू करने पर रोक लगाई जाए।

क्या है नया कानून?

- यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026' लागू कर दिए हैं।
- अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

रूबिक्स डेटा साइंसेज की रिपोर्ट में खुलासा, भारत-ईयू एफटीए से निर्यात क्षेत्र को मजबूती

11 अरब डॉलर तक लाभ होने की संभावना

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) से भारतीय निर्यातकों के लिए 10-11 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात के अवसर खुलेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में दी गई। रूबिक्स डेटा साइंसेज की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इस अतिरिक्त निर्यात को बिना क्षमता बढ़ाए केवल अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुए निर्यात रिडायरेक्ट करके पूरी कर सकता है।

भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में टॉप 15 उत्पाद श्रेणी का हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है, जिसकी वैल्यू करीब 45 अरब डॉलर है। इनमें से 12 श्रेणी में करीब 21 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जिनकी अभी ईयू के आयात बास्केट में सीमित मौजूदगी है।

अमेरिकी को 50% निर्यात किए बगैर भारत पा लेगा लक्ष्य

भारत और यूरोपीयन यूनियन का झंडा

ईयू भारत में बड़ा निवेशक

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 21.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देशों का समूह ईयू की वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत पर है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जर्मनी, फ्रांस और इटली में मंदी देखी जा रही है। व्यापार के अतिरिक्त ईयू भारत में बड़ा विदेशी निवेशक है। अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2024 तक ईयू ने भारत में कुल 119.2 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जो कि देश के कुल एफडीआई प्रवाह का 16.5 प्रतिशत है।

भारत को मिलेगा ईयू का बड़ा बाजार

रिपोर्ट में बताया गया कि अगर इन निर्यात का 50 प्रतिशत भी टैरिफ में कमी और बेहतर मार्केट एक्सेस के जरिए धीरे-धीरे ईयू की तरफ मोड़ दिया जाता है, तो यह बदलाव भारत-ईयू व्यापार समीकरण को काफी हद तक बदल सकता है। भारत को ईयू देशों का एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। हालांकि, भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार बीते तीन वर्ष (वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 25) के बीच 136.5 अरब डॉलर पर सपाट बना हुआ है। वित्त वर्ष 25 में ईयू, यूएस को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय साझेदार था।

भारत से 70% निर्यात ईयू के 5 देशों को

भारत की ईयू के आयात में हिस्सेदारी सिर्फ 2.9 प्रतिशत और उसके निर्यात में हिस्सेदारी 1.9 प्रतिशत है, जो रणनीतिक इरादे और असल में हुए ट्रेड नतीजों के बीच के अंतर को दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ईयू को ट्रेड फ्लो भी बहुत ज्यादा केंद्रित है, जिसमें भारत का ईयू को होने वाला 70 प्रतिशत से ज्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ पांच सदस्य देशों को होता है।

केंद्र के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा

विदेशों में छिपे 71 भगोड़े ट्रेस हुए 47 अनुरोधों पर कार्रवाई की मंजूरी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पिछले एक साल में सीबीआई को भगोड़ों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत को वांछित 70 से ज्यादा अपराधियों और भगोड़ों को विदेशों में ढूंढ लिया गया है। वहीं, इसी दौरान भारत में छिपे दूसरे देशों के 203 भगोड़ों का भी पता लगाया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024-25 के दौरान कुल 71 भगोड़ों की लोकेशन विदेशों में ट्रेस की गई। विदेशों में छिपे भारतीय भगोड़ों को ना केवल ट्रेस किया गया, बल्कि पिछले वित्तीय वर्ष में 27 भगोड़ों को विदेश से भारत वापस भी लाया गया है। भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी के तौर पर काम करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इन अपराधियों को वापस लाने के लिए काम कर रही है। भारत ने विदेशों से कानूनी मदद मांगने के लिए 74 न्यायिक अनुरोध भेजे। इनमें से 47 अनुरोधों को मंजूरी मिली है। इनमें से 54 सीबीआई के मामलों से जुड़े थे और 20 राज्यों की कानून प्रवर्तन और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई)

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक देवेन्द्र सिंह द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड़, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 से प्रकाशित। संपादक : डॉ. हिमांशु द्विवेदी। RNI No. 63924/1996, फोन : 9253681019-20, फैक्स : 274202, e-mail : rohtak@haribhoomi.com, rohtakharibhoomi@gmail.com
Postal Regd. No. P/RTK/389/2026-28